

किसान क्रेडिट कार्ड ने किसानों को दी राहत: शिवराज चौहान



टीम एक्शन इंडिया नई दिल्ली। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों को साहूकारी, ऊँचे ब्याज, जटिल कर्ज प्रक्रिया से राहत दिलाने के लिए कृषि वित्त तंत्र को और अधिक सरल, व्यावहारिक, मानवीय और परिणामोन्मुख बनाना होगा। उन्होंने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड ने किसानों को राहत दी है लेकिन आवश्यकता है कि तकनीक का विवेकपूर्ण उपयोग हो, बैंकिंग व्यवस्था ग्रामीण जरूरतों के अनुरूप मजबूत बने, योजनाएं जमीन पर व्यावहारिक रूप से लागू हों। जिससे छोटे किसानों को आय बढ़ाने के लिए एकीकृत खेती जैसे मॉडल को आगे बढ़ाया जा सके। सिविल सेवा दिवस के अवसर पर मंगलवार को विज्ञान भवन में कृषि पर आयोजित पैनल चर्चा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान ने कहा कि केसीसी और बैंकिंग ऋण सुविधाओं ने किसानों को राहत पहुंचाई है।

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

एक्शन इंडिया

वर्ष: 20 अंक: 112 पृष्ठ: 12

RNI : DELHIN/2006/19302

 actionindianews@gmail.com

राष्ट्रीय संस्करण

दिल्ली - हरियाणा - हिमाचल प्रदेश - उत्तराखण्ड - चंडीगढ़

दिल्ली की पांच लाख महिलाओं को मिला पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता



टीम एक्शन इंडिया नई दिल्ली। दिल्ली सरकार की 'पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड' योजना के तहत अबतक 5 लाख से अधिक महिलाओं को कार्ड जारी किए जा चुके हैं। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार कुल 5 लाख 30 हजार महिलाओं ने इस सुविधा को अपनाया है, जिसमें से सभी कार्ड वर्तमान में सक्रिय रूप से उपयोग किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को एक विज्ञापि जारी करते हुए कहा कि यह न केवल इस योजना की सफलता को प्रमाणित करती है, बल्कि दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था पर महिलाओं के बढ़ते भरोसे और सक्रिय भागीदारी को भी दर्शाती है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार दिल्ली की हर बेटी और महिला की सुरक्षा, सुविधा और आत्मनिर्भरता के लिए प्रतिबद्ध है। 'पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड' केवल मुफ्त यात्रा का पास नहीं है, बल्कि यह महिलाओं को एक डिजिटल पहचान और सम्मानजनक सफर का अनुभव देने वाला सशक्त माध्यम है। जब परिवहन सुलभ और सुरक्षित होता है तो महिलाओं के लिए शिक्षा, रोजगार और प्रगति के अवसर अपने आप ही बढ़ जाते हैं। इस पहल से महिलाएं

आत्मनिर्भरता

सरकार दिल्ली की हर बेटी और महिला की सुरक्षा, सुविधा और आत्मनिर्भरता के लिए प्रतिबद्ध है : रेखा गुप्ता

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह 'टैप-एंड-गो' तकनीक पर आधारित एनसीएमसी कार्ड है। अब महिलाओं को कागजी टिकट लेने की जरूरत नहीं है। केवल ईटीएम मशीन पर कार्ड टैप करें और अपनी

सीट लें। इस कार्ड की मदद से महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों को बस में मुफ्त यात्रा करने की सुविधा मिल रही है। साथ ही यही स्मार्ट कार्ड भुगतान देकर मेट्रो और अन्य पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। यह योजना 5 वर्ष से अधिक उम्र की दिल्ली की सभी महिलाओं और ट्रांसजेंडर निवासियों के लिए है। इतना ही नहीं, कार्ड को आसानी से ऑनलाइन रिचार्ज किया जा सकता है और यात्रा का विवरण ट्रैक किया जा सकता है, जिससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और कुशल बन गई है।

फास्ट न्यूज

आयात घटाना और प्रदूषण कम करना सरकार की प्राथमिकता: गडकरी

नई दिल्ली। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवाक तो कहा कि देश का परिवहन पारिस्थितिकी तंत्र आधुनिक, सुरक्षित और टिकाऊ बनाने की दिशा में सरकार तेजी से काम कर रही है। सरकार का उद्देश्य आयात कम करना, सस्ता और प्रदूषण मुक्त परिवहन उपलब्ध कराना तथा इसे स्वदेशी बनाना है। गडकरी ने यहां इंडिया हैबिटाट सेंटर में इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी (आईएफजीई) के ग्रीन ट्रांसपोर्ट कॉन्फ्लेव- सस्टेनेबल और ग्रीन मोबिलिटी के भविष्य की ओर तेजी कार्यक्रम में कहा कि आज देश में कुल ईंधन की जरूरत का 87 फीसदी आयात किया जाता है, जिसकी कीमत लगभग 22 लाख करोड़ रुपये है। पश्चिम एशिया संकट के चलते इस आयात पर निर्भरता के परिणाम देश को भुगतने पड़ रहे हैं। आत्मनिर्भर बनना ही सबसे बड़ा उद्देश्य है। नई तकनीक आने से पुराने उद्योगों में असुरक्षा की भावना पैदा होती है, इसके बावजूद आयात कम करना बेहद कठिन है।

'मैंने यह नहीं कहा कि प्रधानमंत्री एक आतंकवादी हैं, मेरे कहने का मतलब यह था कि वह लोगों को डराने-धमकाते हैं'

मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री मोदी को बता दिया 'आतंकी'

आपत्तिजनक

खरगे मोदी के खिलाफ अपनी एक कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर विवादों के केंद्र में हैं

टीम एक्शन इंडिया चेन्नई: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपनी एक कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर विवादों के केंद्र में हैं। दरअसल एक रैली में उन्होंने पहले पीएम मोदी की तुलना आतंकवादी से कर दी। हालांकि बाद में सफाई देते हुए अपना बचाव किया है। इस पूरे घटनाक्रम ने चुनावी माहौल में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग को और भी तीखा कर दिया है।

खरगे ने प्रधानमंत्री के बारे में असल में क्या कहा था?

चेन्नई में कार्यक्रमों को संबोधित करते हुए मल्लिकार्जुन खरगे ने अन्नाद्रमुक के भाजपा के साथ गठबंधन करने पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कड़े लहजे में कहा कि अन्नाद्रमुक के लोग मोदी के साथ कैसे जुड़ सकते हैं, जबकि वे समानता और न्याय में विश्वास नहीं रखते। खरगे ने आगे कहा कि ऐसे लोगों के साथ हाथ मिलाना लोकतंत्र को कमजोर करने जैसा है। इसी दौरान उन्होंने

मल्लिकार्जुन खरगे ने सरकारी संस्थाओं के दुरुपयोग का आरोप लगाया?

अपनी सफाई के दौरान खरगे ने सीधे तौर पर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री पर सरकारी संस्थाओं के दुरुपयोग का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ईडी, आयकर विभाग और सीबीआई जैसी महत्वपूर्ण संस्थाएं पूरी तरह से प्रधानमंत्री के हाथों में हैं और इनका इस्तेमाल विरोधियों को डराने के लिए किया जा रहा है। खरगे ने यह भी विंता जताई कि प्रधानमंत्री परिसीमन जैसी प्रक्रियाओं को भी अपने नियंत्रण में लेना चाहते हैं।

मोदी को गाली देना कांग्रेस की

आतंकवादी हैं। मेरे कहने का मतलब यह था कि वह लोगों और राजनीतिक दलों को डराने-धमकाने का काम करते हैं। खरगे ने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री मोदी हमेशा धमकियां देते हैं और उनके आचरण से राजनीतिक गलियारों में डर पैदा होता है। उन्होंने यह भी कहा कि

उनकी टिप्पणी का उद्देश्य प्रधानमंत्री की कार्यशैली पर सवाल उठाना था, न कि उन पर कोई व्यक्तिगत हमला करना। अपनी सफाई के दौरान खरगे ने सीधे तौर पर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री पर सरकारी संस्थाओं के दुरुपयोग का आरोप लगाया।

प्रधानमंत्री से मिले बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विकास को लेकर चर्चा।



भारत-भूटान सीमा शुल्क बैठक में व्यापार सुगमता और सीमा प्रबंधन पर सहमति

मुन्नार (केरल)। भारत और भूटान के बीच 20-21 अप्रैल को मुन्नार में आयोजित सातवीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह (जेजीसी) बैठक में सीमा शुल्क सहयोग, व्यापार सुगमता और सीमा प्रबंधन को मजबूत करने पर सहमति जताई गई। बैठक में तत्कालीन रोकथाम, सीमा शुल्क प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण, सीमा अवसरंचना सुधार और इलेक्ट्रॉनिक कार्गो ट्रैकिंग सिस्टम के तहत माल आवाजाही सुगम बनाने जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और बढ़ाने तथा सुरक्षित सीमा प्रबंधन सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता दोहराई। अध्यक्षता भारत सरकार के केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के विशेष सचिव और सदस्य (सीमा शुल्क) योगेन्द्र गर्ग तथा भूटान के वित्त मंत्रालय के राजस्व एवं सीमा शुल्क विभाग के महानिदेशक सोनम जाम्तेशो ने की।

रूस बना भारत का सबसे बड़ा कूड ऑयल सप्लायर

टीम एक्शन इंडिया नई दिल्ली: पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण खाड़ी के देशों से होने वाले कूड ऑयल (कच्चे तेल) के आयात पर काफी बुरा असर पड़ा है। इस युद्ध के कारण खाड़ी देशों से होने वाले कूड ऑयल के आयात में लगभग 61 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। इस तनाव के बीच इंडियन ऑयल रिफाइनरीज के लिए रूस एक बार फिर सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर

बन कर सामने आया है। इसी तरह अफ्रीकी देश अंगोला ने भी मार्च के महीने में खाड़ी के कई देशों को पीछे छोड़ कर भारत को जम कर कूड ऑयल की सप्लाई की है। पश्चिम एशिया में जारी जंग के कारण मार्च महीने में भारत के कुल कूड ऑयल इंपोर्ट में फरवरी की तुलना में लगभग 13 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। खाड़ी देशों से होर्मुज स्ट्रेट के रास्ते होने वाली कूड ऑयल की सप्लाई लगभग ठप हो गई है।

उप मुख्यमंत्री साव ने की नगर पंचायतों के कार्यों की समीक्षा

रायपुर: प्रदेशभर के नगरीय निकायों की समीक्षा का दौर आज दूसरे दिन भी जारी रहा। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने रायपुर के सिविल लाइन स्थित सफ़िंट हाउस में आज दिनभर चली बैठक में सभी नगर पंचायतों के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने बैठक में नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को बेतरतीब निमाणी, अवैध प्लॉटिंग और अतिक्रमण पर सख्ती से रोक लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने नगर पंचायतों के कार्यों और व्यवस्थाओं में कसावट लाने को कहा। श्री साव ने कहा कि काम में लापरवाही और कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जवाबदेही तय कर संबंधितों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

उर्जा सुरक्षा, आपूर्ति शृंखलाओं को सुचारु बनाए रखने को समन्वित प्रयास: केंद्र

टीम एक्शन इंडिया नई दिल्ली। पश्चिम एशिया संकट के बीच केंद्र सरकार ने कहा कि देश में बंदरगाह संचालन, ऊर्जा आपूर्ति और डेयरी क्षेत्र सामान्य रूप से काम कर रहे हैं। भारतीय नाविक सुरक्षित हैं, दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों की कीमतें स्थिर हैं तथा समुद्री बीमा के लिए विशेष फंड की व्यवस्था की गई है। उर्जा सुरक्षा, भारतीय प्रवासी समुदाय के कल्याण और आपूर्ति शृंखलाओं को सुचारु बनाए रखने के लिए समन्वित प्रयास किए जा रहे हैं। बंदरगाह, जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव मुकेश मंगल ने यहां मंगलवार को राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में आयोजित अंतरमंत्रालयी पत्रकार वार्ता में कहा कि पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाहों पर कंटेनर वॉल्यूम में भारी गिरावट दर्ज की गई है। आठ मार्च को जहां लगभग 3,383 कंटेनर थे, वहीं अब यह घटकर मात्र 99 रह गए हैं।

पंजाब में आज भी नीतियां केवल घोषणाओं तक सीमित: सैनी

टीम एक्शन इंडिया चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि भाजपा की राजनीति का आधार वोट नहीं, बल्कि हर नागरिक का सम्मान और उसका विकास है। सरकार तुष्टिकरण की नहीं, बल्कि सशक्तिकरण की दिशा में कार्य करती है। यह सरकार वोट बैंक नहीं बनाती बल्कि विकास बैंक बनाती है। उन्होंने कहा कि पंजाब की जनता बदलाव के लिए तत्पर रहे और पंजाब को खुशहाल बनाने की दिशा में कार्य करें। भाजपा की

सरकार बनने पर पंजाब में नशे का धंधा करने वाले पंजाब छोड़कर भाग जाएंगे। मुख्यमंत्री ने यह बात मोलवार को संत कबीर कुटीर चण्डीगढ़ में आए ह्याय सिख समाजह्व के प्रतिनिधि मंडल को सम्बोधित करते हुए कही। नायब सिंह सैनी ने कहा कि पंजाब सरकार ने केवल लुभावने वादे किए, वहीं वर्तमान हरियाणा सरकार ने धरातल पर आरक्षण के अंदर आरक्षण लागू कर यह सुनिश्चित किया है कि राय सिख युवाओं को सरकारी तंत्र और प्रशासन में उनकी

मुख्यमंत्री ने ज्वालामुखी में विद्युत मंडल और उपमंडल कार्यालय भवन के निर्माण कार्य का किया शिलान्यास

मुख्यमंत्री सुखविन्द सिंह सुक्खू ने देहरिया में उपमंडल खोलने की घोषणा की

शिलान्यास

मुख्यमंत्री सुक्खू ने 33 केवी सब-स्टेशन के सुदृढीकरण कार्य का शिलान्यास किया

टीम एक्शन इंडिया विजय समयाल कांगड़ा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द सिंह सुक्खू ने कांगड़ा जिला के ज्वालामुखी में विद्युत मंडल एवं उपमंडल कार्यालय भवनों के निर्माण कार्य तथा 33 केवी सब-स्टेशन के सुदृढीकरण

कार्य का शिलान्यास किया। इन दोनों विकाससात्मक परियोजनाओं की अनुमानित लागत लगभग 4 करोड़ रुपये है और इन परियोजनाओं से विभिन्न वर्गों और जल शक्ति विभाग की योजनाओं से 35,000 से अधिक

उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। इस अवसर मुख्यमंत्री ने ज्वालामुखी के देहरिया में एक और विद्युत उपमंडल खोलने की घोषणा की, जिसके लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे क्षेत्र में वोलटेज

की समस्या का समाधान सुनिश्चित होगा और उपभोक्ताओं को सप्ताहभर निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के लिए पूर्व में 48 करोड़ रुपये की लागत से नौ 33 केवी विद्युत उपमंडल की घोषणा की गई है जिनका निर्माण कार्य विभिन्न चरणों में प्रगति पर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार श्री ज्वालामुखी, श्री चित्तपूर्णी जी और श्री नैना देवी में धार्मिक पर्यटन के विकास के लिए एक मास्टर प्लान के तहत काम कर रही है। उन्होंने कहा कि श्री ज्वालामुखी और श्री नैना देवी के सौंदर्यीकरण पर 150

करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे तथा पहले चरण में इन कार्यों के लिए 25 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी करने की घोषणा की गई इससे पहले मुख्यमंत्री ने ज्वालामुखी मंदिर में पूजा अर्चना की और विभिन्न स्थानों पर चल रहे सौंदर्यीकरण कार्यों का निरीक्षण भी किया। स्थानीय विधायक संजय रत्न ने विभिन्न विकाससात्मक परियोजनाओं के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में उनके क्षेत्र में करोड़ों रुपये के विकास कार्य जन समर्पित किए गए हैं।

पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु में चुनाव प्रचार थमा, 23 अप्रैल को मतदान

टीम एक्शन इंडिया नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में गुरुवार को होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार मंगलवार शाम 5 बजे थम गया। पश्चिम बंगाल के पहले चरण के लिए 152 सीटों और तमिलनाडु की सभी 234 सीटों पर 23 अप्रैल को मतदान होगा। चुनाव आयोग के अनुसार मंगलवार शाम 5 बजे से दोनों राज्यों में चुनाव प्रचार पूरी तरह थम गया और साइलेंस पेरियड लागू हो गया। नियमों के मुताबिक मतदान से 48 घंटे पहले प्रचार अभियान पर पूर्ण प्रतिबंध लागू

जनसेवा

भाजपा की राजनीति का आधार वोट बैंक नहीं, बल्कि जन जन का सम्मान व विकास है : मुख्यमंत्री

आबादी के अनुसार उचित प्रतिनिधित्व मिले। जब हम पंजाब की स्थिति से तुलना करते हैं, तो हरियाणा में सुशासन का मॉडल सेवा का उत्कृष्ट उदाहरण है।

सोशल मीडिया पर प्रचार किया जा सकता है। नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान है। मतदान को बढ़ावा देने और 100 प्रतिशत मतदान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चुनाव आयोग ने राज्यभर में व्यापक जागरूकता अभियान शुरू किए हैं। तमिलनाडु में इस बार कुल 4,023 उम्मीदवार मैदान में हैं। यहां मुख्य मुकाबला द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (द्रमुक) और अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (अन्नाद्रमुक) के नेतृत्व वाले गठबंधन के बीच माना जा रहा है।

उत्तर प्रदेश में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध योगी सरकार

❑ 40 लाख से अधिक को मिल रहा विधवा पेंशन का लाभ ❑ निराश्रित महिला (विधवा) पेंशन योजना अहम भूमिका निभा रही है। इस योजना के तहत प्रदेश की 40.32 लाख से अधिक विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जा रही ❑ इस योजना के जरिए उन महिलाओं तक सीधी मदद पहुंचायी जा रही है, जिनके सामने पति के निधन के बाद आजीविका का संकट खड़ा हो जाता है

लाभ

❑ महिला कल्याण विभाग की इस योजना के तहत प्रदेश की कुल 40,32,629 महिलाओं को लाभ मिला है

टीम एक्शन इंडिया लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और सुरक्षा के स्तर पर मजबूत बनाने के लिए लगातार कई योजनाएं चला रही है। इसी कड़ी में निराश्रित महिला (विधवा) पेंशन योजना अहम भूमिका निभा रही है। इस योजना के तहत प्रदेश की 40.32 लाख से अधिक विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जा रही है। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि इस योजना के जरिए उन महिलाओं तक सीधी मदद पहुंचायी जा रही है, जिनके सामने पति के निधन के बाद आजीविका का संकट खड़ा हो जाता है। महिला कल्याण विभाग की इस योजना के तहत प्रदेश की कुल 40,32,629 महिलाओं को लाभ मिला है। यह पेंशन सालभर में चार किस्तों में जारी की जाती है, जिसमें हर तीन महीने की राशि एक साथ दी जाती है। इसमें



होमगार्ड भर्ती परीक्षा और कानून व्यवस्था पर मुख्यमंत्री योगी 22 को करेंगे समीक्षा बैठक

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में होने वाली होमगार्ड भर्ती परीक्षा को लेकर राज्य सरकार पूरी तरह अलर्ट है। इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार रात नौ बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के सभी वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों के साथ व्यापक समीक्षा करेंगे। परीक्षा की तैयारियों के साथ-साथ कानून व्यवस्था को लेकर भी मुख्यमंत्री महत्वपूर्ण निर्देश देंगे।

अप्रैल-मई-जून, जुलाई-अगस्त-सितंबर, अक्टूबर-नवंबर-दिसंबर और जनवरी-फरवरी-मार्च की किस्तें शामिल हैं। साल 2021 में विधवा पेंशन को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए सहायता राशि को

500 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया गया था। यह राशि सीधे लाभार्थियों के आधार लिंक बैंक खातों में पीएफएमएस के माध्यम से ट्रांसफर की जाती है, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित होती

है। उन्होंने बताया कि आंकड़ों पर नजर डालें तो वर्ष 2016-17 से पहले जहां करीब 17.31 लाख महिलाएं इस योजना का लाभ ले रही थीं, वहीं अब यह संख्या बढ़कर 40.32 लाख से अधिक

हो चुकी है। यह विस्तार दशार्ता है कि सरकार लगातार ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद महिलाओं को योजना से जोड़ रही है। योजना के तहत सिर्फ वही महिलाएं पात्र हैं जो उत्तर प्रदेश की स्थायी निवासी

हों। साथ ही जिनके पति का निधन हो चुका हो, जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो और परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपये से कम हो उन्हें ही लाभ मिल सकता है।

श्री रामजन्मभूमि परिसर में बने शिव मंदिर के शिखर पर 29 अप्रैल को धर्म ध्वजा फहराएंगे मुख्यमंत्री योगी



अयोध्या: श्री राम नगरी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में बने शिव मंदिर के शिखर पर 29 अप्रैल को ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 29 अप्रैल को सायंकाल 5 बजे ध्वजारोहण करेंगे। इस अवसर पर बड़ी संख्या में विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहेंगे। राम मंदिर ट्रस्ट के विशेष आमंत्रित सदस्य गोपाल राव ने मंगलवार को इस कार्यक्रम की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री को आधिकारिक रूप से आमंत्रित किया गया है और उनके हाथों से ही पूरा कार्यक्रम संपन्न होगा। इस अवसर पर भाजपा के कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लगभग 1000 स्थानीय कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। उन्होंने बताया कि ध्वजारोहण कार्यक्रम से पहले मुख्यमंत्री हनुमान गढ़ी और रामलला का दर्शन-पूजन करेंगे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री जनसभा को संबोधित भी करेंगे। शिव मंदिर परकोटा के उत्तर-पूर्वी कोने पर मंच तैयार किया जाएगा। परकोटा के पूर्वी हिस्से में वीआईपी अतिथियों के बैठने की व्यवस्था की जाएगी। यहां से सभी लोग ध्वजारोहण कार्यक्रम का सीधा दर्शन कर सकेंगे।

पूर्णिया लेंसकार्ट शोरूम में श्री राम सेवा संघ ने कर्मियों को तिलक लगाया

नारे लगाए

❑ बड़ी कंपनियों को किसी एक समुदाय के पक्ष या विरोध में खड़ा नहीं होना चाहिए: श्री राम सेवा संघ



टीम एक्शन इंडिया पूर्णिया। बिहार में पूर्णिया शहर के लेंसकार्ट शोरूम में मंगलवार को श्री राम सेवा संघ के सदस्यों द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें वहां कार्यरत कर्मचारियों को टीका(तिलक) लगाया गया और 'जय श्री राम' के नारे लगाए गए। इस दौरान संगठन के राणा प्रताप सिंह, कुंदन मंडल, गोलू जायसवाल, आदित्य कर्ण

समेत कई लोग मौजूद रहे और सभी कर्मचारियों के साथ मिलकर आपसी भाईचारे का संदेश दिया। कार्यक्रम के दौरान राणा प्रताप सिंह ने कहा कि देश में व्यवसाय धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बड़ी कंपनियों को किसी एक समुदाय के पक्ष या विरोध में खड़ा नहीं होना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी तरह की एकाधिकार (मोनोपॉली) की

स्थिति को न तो देश में और न ही बिहार या पूर्णिया में स्वीकार किया जाएगा। दो दिनों के अंदर लेंसकार्ट के सीओ को देश और हिन्दू समाज से माफी मांगना चाहिए। अन्यथा और बड़ा आंदोलन होगा। शोरूम के फ्रेंचाइजी संचालक केशव पंसारि ने इन कहा कि उनके यहां सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर काम करते हैं। किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता।

टीम एक्शन इंडिया जालंधर: सुंदरम फाइनेंस की जालंधर शाखा ने आज अपनी सेवा के 25 वर्ष पूरे कर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है, इस उपलब्धि पर एक बड़ा जश्न मनाया गया। यह जश्न केवल 25 वर्ष पूरे होने का नहीं, बल्कि ग्रहकों के साथ स्थायी साझेदारी, कर्मचारियों के समर्पण और उनके परिवारों के सहयोग को मान्यता देने का उत्सव भी था, जिन्होंने जालंधर की इस शाखा की विरासत को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पंजाब क्षेत्र में सुंदरम फाइनेंस के सीनियर जीएम एवं हेड सलील नायर ने कहा, सुंदरम फाइनेंस के इस लम्बे सफर का श्रेय -सच्चाई, निष्पक्षता और उस सेवा भाव को जाता है जिसकी डोर से हम अपने ग्राहकों के साथ बंधे हैं। यह शाखा अपने मूल्यों और उस समुदाय के बलबूते टिकी हुई है जिसे हम सेवा

साझेदारी, कर्मचारियों के समर्पण और उनके परिवारों के सहयोग को मान्यता देने का उत्सव भी था

प्रदान करते और जिसके साथ जुड़े हैं। "1997 में स्थापित, जालंधर शाखा ने जालंधर में वित्तीय पहुँच का विस्तार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और हमेशा से ऐसे ग्राहकों को सेवाएँ प्रदान की हैं जो मुख्यधारा के वित्तीय समाधानों की पहुँच से बाहर थे। चाहे वह कोई छोटा मोटा व्यवसाय चलाने वाला, पहली बार ऋण लेने वाला व्यक्ति हो, न्य नियोजित पेशेवर या परिवहन संचालक हो, सभी को इस शाखा में अपना एक भरोसेमंद वित्तीय साझेदार मिला है।"

टीम एक्शन इंडिया पटना। जनता दल यूनाइटेड (जदयू) प्रदेश प्रवक्ता हिमराज राम एवं प्रदेश प्रवक्ता परिमल कुमार ने जारी बयान में कहा कि नीतीश कुमार के शासनकाल के दौरान बिहार ने पिछले दो दशकों में जिस परिवर्तनकारी यात्रा को तय किया है, वह दूरदर्शी नेतृत्व, पारदर्शी नीतियों और जनसेवा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का परिणाम है। सीमित संसाधनों के बावजूद आम जनमानस के जीवन को बेहतर बनाने का जो संकल्प लिया गया, उसे सड़कों, पुलों, बिजली आपूर्ति और नल-जल जैसी मूलभूत सुविधाओं के विस्तार के माध्यम से साकार किया गया। यह बदलाव केवल ढांचगत विकास तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने राज्य के



सामाजिक और आर्थिक आत्मविश्वास को भी नई दिशा दी है। जहां एक ओर राजनीति को निजी लाभ का माध्यम बनाने की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। उन्होंने कहा नीतीश कुमार ने सुशासन और जवाबदेही की नीति ने जनता के बीच विश्वास का एक मजबूत आधार खड़ा किया। यही विश्वास आज सबसे बड़ी पूंजी के रूप में सामने आया है,

जिसने सरकार और जनता के रिश्ते को और अधिक सुदृढ़ किया है। सुशासन की सोच के साथ नीतीश कुमार की लागू की गई नीतियों ने एक ऐसे नए बिहार की नींव रखी है, जो विकास, समावेशन और अवसरों की समानता के सिद्धांतों पर आधारित है। इसी मजबूत आधार के कारण आज बिहार निरंतर प्रगति की दिशा में अग्रसर है।

अल्ट्राटेक ने भारत में 200 मिलियन टन प्रति वर्ष क्षमता का आंकड़ा पार किया

टीम एक्शन इंडिया शिमला: आदित्य बिड़ला समूह की प्रमुख सीमेंट कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड ने घोषणा की है कि उन्होंने भारत में 200से ज्यादा मिलियन टन प्रति वर्ष स्थापित सीमेंट निर्माण क्षमता का आंकड़ा पार कर लिया है। कंपनी ने तीन नई सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट्स शुरू की हैं, जिनकी कुल क्षमता 8.7 मिलियन टन प्रति वर्ष है। इसके साथ ही, अल्ट्राटेक चीन को छोड़कर, बिक्री की मात्रा और क्षमता के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी बन गई है। इन नई यूनिट्स के जुड़ने के बाद अल्ट्राटेक की भारत में कुल क्षमता 200.1 मिलियन टन

प्रति वर्ष हो गई है, जबकि वैश्विक स्तर पर इसकी संयुक्त क्षमता 205.5 मिलियन टन प्रति वर्ष तक पहुंच गई है। इसमें संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और श्रीलंका में संचालित यूनिट्स से 5.4 मिलियन टन प्रति वर्षक्षमता शामिल है। अल्ट्राटेक की वृद्धि केवल आकार में ही नहीं, बल्कि गति में भी उल्लेखनीय रही है। कंपनी को 100 मिलियन टन प्रति वर्ष तक पहुंचने में 36 वर्ष लगे थे, जो उपलब्धि उसने 2019 में हासिल की थी। इसके बाद अगले 100 मिलियन टन प्रति वर्ष तक पहुंचने में उसे सात वर्ष से भी कम समय लगा।

'पंख अभियान' से बदली नीमच जिले के बेटियों की किस्मत

टीम एक्शन इंडिया भोपाल। जब इरादे मजबूत हों और प्रशासन का सहयोग मिले, तो सदियों पुरानी बेड़ियां भी टूट जाती हैं। इसका उदाहरण नीमच जिले में देखने को मिला। यहां जिला प्रशासन की अभिनव पहल 'पंख अभियान' आज बांछड़ा समुदाय की उन बेटियों के लिए उम्मीद का उजाला बनकर उभरा है, जो कभी सामाजिक बहिष्कार और पीढ़ीगत मजबूरियों के अंधेरे में खोई हुई थीं। दरअसल, बांछड़ा समुदाय ऐतिहासिक रूप से आर्थिक अभाव और कुछ शोषणकारी सामाजिक कु-प्रथाओं के कारण हाशिए पर रहा है। यहां की बालिकाओं के लिए 'देह-व्यापार'



जैसी मजबूरियां उनके भविष्य के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा थीं। लेकिन 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' की मूल भावना को धरातल पर उतारते हुए नीमच जिला प्रशासन ने "पंख" अभियान के माध्यम से इस अभिशाप को गरिमा में बदलने का बीड़ा उठाया है।

वर्दी पहनने का सपना हो रहा साकार

जनसंपर्क अधिकारी बिन्दु सुनील ने मंगलवार को जानकारी देते हुए बताया कि अभियान की सबसे बड़ी उपलब्धि 'सशक्त वाहिनी' योजना है। जहां कल तक इन गलियों में अशुभ्रक्षा का साथ था, आज वहां की 14 बेटियां पुलिस

'सशक्त वाहिनी'

❑ आज वहां की 14 बेटियां पुलिस और अर्धसैनिक बलों में भर्ती होने के लिए पसीना बहा रही हैं

और अर्धसैनिक बलों में भर्ती होने के लिए पसीना बहा रही हैं। प्रशासन इन्हें न केवल निःशुल्क शैक्षणिक मार्गदर्शन दे रहा है, बल्कि शारीरिक प्रशिक्षण के माध्यम से उन्हें देश सेवा के लिए तैयार कर रहा है। यह केवल एक प्रशिक्षण नहीं, बल्कि उनके आत्मसम्मान की बहाली है।

राज्यपाल पटेल ने विशेष योगदानकर्ताओं के अभिनंदन समारोह को किया संबोधित, दान अंतरात्मा की आवाज है, यह आत्मीय भाव से की गयी सहयोग की पहल है

सशस्त्र सेना झंडा निधि में योगदान, राष्ट्र भक्ति की सशक्त अभिव्यक्ति: राज्यपाल

मानवीय धर्म

❑ राष्ट्र धर्म का पालन करने वाले वीर सैनिकों के त्याग और बलिदान के प्रति आभारी होना हमारा सर्वोच्च मानवीय धर्म है



राज्यपाल पटेल मंगलवार को समामेलित विशेष निधि प्रबंध समिति की बैठक उपरांत लोकभवन में आयोजित सशस्त्र सेना झंडा निधि में सहयोग राष्ट्र देने वालों के अभिनंदन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सशस्त्र सेना झंडा कोष

में उदार योगदान हमारे सैनिकों और उनके परिवारों का केवल आर्थिक सहयोग नहीं, बल्कि राष्ट्रभक्ति की सशक्त अभिव्यक्ति है। झंडा निधि में सहयोग राष्ट्र सेवा में समर्पित वीरों के प्रति हमारे कर्तव्य पालन का अवसर है। राज्यपाल पटेल ने प्रदेशवासियों

का आहवान किया कि सैनिक कल्याण के लिए अपनी क्षमता के अनुसार अधिक से अधिक दान दें। साथ ही अन्य लोगों को भी प्रेरित करें। उन्होंने लक्ष्य से अधिक राशि संग्रहण के लिए संभागयुक्त जबलपुर धनजय सिंह भदौरिया, हरदा कलेक्टर सिद्धार्थ जैन, अलीराजपुर कलेक्टर नीतू माथुर, नीमच कलेक्टर हिमांशु चंद्रा और दानदाताओं को प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव गृह के.सी. गुप्ता, राज्यपाल के प्रमुख सचिव डॉ. नवनीत मोहन कोठारी, सचिव गृह विभाग शिल्पा गुप्ता, जी.ओ.सी. मध्यप्रदेश मेजर

जनरल संजय गौतम, ब्रिगेडियर शरद नायर और विकास बत्रा सहित सैनिक कल्याण बोर्ड मध्यप्रदेश के पदाधिकारी, प्रबंध समिति के सदस्य मौजूद थे। **लक्ष्यों से अधिक राशि संकलन पर दी बधाई**

राज्यपाल पटेल ने अभिनंदन समारोह में निर्धारित लक्ष्यों से अधिक राशि एकत्र करने वाले जिलों की सराहना की। सैनिक कल्याण प्रयासों में सहभागी सभी उपक्रमों, संगठनों और व्यक्तिगत दानदाताओं का आभार भी जताया। राष्ट्रीय सम्मेलन में विगत वर्ष सशस्त्र बलों के पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिये उत्कृष्ट योगदान के लिए मध्यप्रदेश को

सम्मानित किए जाने की बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि केवल प्रशासनिक दक्षता का परिचायक नहीं, बल्कि हमारे समाज की जागरूकता, संवेदनशीलता और देशभक्ति का प्रतीक है। इसके लिए सभी संभाग आयुक्तों, कलेक्टरों तथा प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई दी और आशा जताई कि यह प्रयास निरंतर आगे भी जारी रहेंगे। राज्यपाल पटेल ने कहा कि हमारी शांति और सुरक्षा के लिए परिवार से दूर रहकर राष्ट्र धर्म का पालन करने वाले वीर सैनिकों के त्याग और बलिदान के प्रति आभारी होना हमारा सर्वोच्च मानवीय धर्म है। र

टीम एक्शन इंडिया दतेवाड़ा। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित रहे दतेवाड़ा जिले के लिए 22 अप्रैल का दिन खास होने जा रहा है। क्रिकेट के महान खिलाड़ी दतेवाड़ा प्रवास पर आ रहे हैं। तेंदुलकर दतेवाड़ा प्रवास इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि जहां कभी डर और हिंसा का माहौल था, वहां अब खेल और उम्मीद की नई रोशनी नजर आ रही है। सचिन तेंदुलकर अपने परिवार और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ छिंदनार गांव पहुंचेंगे और एक बड़े खेल प्रोजेक्ट की शुरूआत करेंगे। इंद्रावती नदी के किनारे बसा छिंदनार गांव इन दिनों पूरी तरह बदला हुआ नजर आ रहा है। गांव में उत्साह है, बच्चों के चेहरों पर खुशी है और हर जगह तैयारियों का माहौल है। छिंदनार गांव में एक आधुनिक मल्टी-

स्पोर्ट्स ग्राउंड तैयार किया गया है। इस मैदान को सचिन तेंदुलकर फाउंडेशन और मानदेशी चैम्पियन संस्था के सहयोग से विकसित किया गया है। खास बात यह है कि यहां एक ही परिसर में 16 तरह की खेल सुविधाएं मौजूद हैं। इसमें खो-खो, कबड्डी, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट के साथ-साथ एक्सरसाइज जॉन भी शामिल है। यह मैदान आदिवासी बच्चों और युवाओं के भविष्य को नई दिशा देगा।

सचिन तेंदुलकर सबसे पहले इसी खेल मैदान का उद्घाटन करेंगे। वे बच्चों से मिलेंगे, उनके साथ समय बिताएंगे और पूरे परिसर का निरीक्षण भी करेंगे। छिंदनार के बाद सचिन तेंदुलकर गौदम के पास स्थित पनेड़ा ग्राउंड का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद वे जावंगा एजुकेशन सिटी पहुंचेंगे, जहां ऑडिटोरियम में छात्रों से सीधा संवाद करेंगे।

गांव-गांव तक विकास की गूँज पहुंचाएगा राम-राम हरियाणा: डा. वीरेंद्र सिंह चौहान

भूमिका

जन-जागरुकता को प्रखर करने में सामुदायिक रेडियो की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।



टीम एक्शन इंडिया राजकुमार प्रिंस करनाल। प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान और विकास से जुड़े मुद्दों पर जन-जागरूकता को प्रखर करने में सामुदायिक रेडियो की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। संस्थान द्वारा संचालित रेडियो सेतु कार्यक्रम राम-राम हरियाणा को और अधिक प्रभावी रोचक तथा जनहितकारी बनाने के लिए समय-समय पर सुधार आवश्यक हैं। यह विचार हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान के निदेशक डॉ.

वीरेंद्र सिंह चौहान ने आज प्रदेशभर के सामुदायिक रेडियो संचालकों की कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए व्यक्त किए। राम-राम हरियाणा रेडियो कार्यक्रम से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। कार्यशाला में कार्यक्रम को और अधिक प्रभावशाली बनाने, वर्तमान में आ रही समस्याओं

के समाधान तथा कार्यप्रणाली को बेहतर ढंग से संचालित करने पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में विभिन्न सामुदायिक रेडियो स्टेशनों से जुड़े प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिनमें सांझा रेडियो यमुनानगर से डॉ. मनमोहन सिंह, इरादा रेडियो थानेसर से राजपाल पांचाल, रेडियो वितस्ता 90.0 से भारत सोपौरी, रेडियो एनजीएफ से

जितेश पोसवाल, तथा संस्थान की ओर से सहायक आचार्य सुशील मेहता, संदीप कुमार, कमलदीप सांगवान एवं राष्ट्रीय ग्रामीण विकास विभाग से वरिष्ठ सलाहकार गुरबिंदर सिंह शामिल रहे। कार्यशाला के दौरान राम-राम हरियाणा कार्यक्रम के प्रसारण समय में संभावित बदलाव पर भी विचार-विमर्श किया गया। फिलहाल कार्यक्रम सुबह 9 बजे से 9.30 बजे तक प्रसारित होता था, जिसमें श्रोताओं की सुविधा और सहभागिता बढ़ाने के लिए समय में परिवर्तन की संभावनाओं पर चर्चा की गई। 29 अप्रैल से कार्यक्रम का संचालन एक घंटा करने का निर्णय लिया गया। इसी दिन से कार्यक्रम शाम चार बजे से पांच बजे प्रसारित हुआ करेगा। इसके अतिरिक्त कार्यक्रम की विषय वस्तु को और अधिक जन

सरोकारों से जोड़ें, तकनीकी गुणवत्ता सुधारने तथा श्रोताओं की प्रतिक्रिया को शामिल करने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी सुझाव प्रस्तुत किए गए। सभी प्रतिभागियों ने अपने-अपने अनुभव साझा करते हुए कार्यक्रम की पहुंच बढ़ाने, स्थानीय मुद्दों को प्राथमिकता देने और बेहतर समन्वय के माध्यम से इसे प्रदेश स्तर पर और अधिक लोकप्रिय बनाने पर बल दिया। बैठक में निदेशक डॉ. वीरेंद्र सिंह चौहान ने सभी सुझावों को गंभीरता से लागू करने का आश्वासन दिया तथा कहा कि सामुदायिक रेडियो के माध्यम से जन जागरूकता और विकास के संदेश को हर घर तक पहुंचाना संस्थान की प्राथमिकता है। उन्होंने सभी प्रतिभागियों का धन्यवाद करते हुए भविष्य में भी इसी प्रकार के सहयोग की अपेक्षा व्यक्त की।

कम लिंगानुपात वाले गांवों पर करें फोकस: राहुल रईया

बैठक

बैठक में उप सिविल सर्जन डॉ. शशि गर्ग, सीडीपीओ संतोष गिरधर, रितु मेहला भी मौजूद रही



टीम एक्शन इंडिया राजकुमार प्रिंस करनाल। जिला टास्क फोर्स कमेटी की एक बैठक जिला सचिवालय सभागार में अतिरिक्त उपायुक्त डा. राहुल रईया की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इसमें जिला में लिंगानुपात पर विचार-विमर्श किया गया। साथ ही कम लिंगानुपात वाले गांवों में सुधार के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश स्वास्थ्य अधिकारियों को दिए। बैठक में उप सिविल सर्जन (परिवार नियोजन) डा. शीनू चौधरी ने बताया कि मार्च तक जिला में लिंगानुपात 984 रहा, जबकि गत वर्ष यह 944 था। उन्होंने बताया कि जिला में

पंजीकृत अल्ट्रासाउंड केंद्रों की संख्या 100 है लेकिन क्रियाशील 98 हैं। पिछली तिमाही में 78 केंद्रों का निरीक्षण किया गया। उन्होंने बताया कि जिला में 11 ब्लाक के तहत 8 सीएचसी, 28 पीएचसी हैं। नीलोखेड़ी, असंध और इंद्री में अस्पताल हैं। पीएचसी स्तर पर भी लिंगानुपात का आकलन किया जाता है। उन्होंने बताया कि जो गांव लिंगानुपात के मामले में अग्रणी रहता है, उसकी तीन मेधावी विद्यार्थियों को बेस्ट व्लेज अवार्ड के तहत सम्मानित भी किया जाता है। कहीं कोई बड़ी अनियमितता सामने नहीं आई। इस पर डा. राहुल ने हर तिमाही में सभी केंद्रों का निरीक्षण सुनिश्चित करने के

निर्देश दिए। साथ ही अगली बैठक में इस बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करने को भी कहा। डा. शीनू चौधरी ने बताया कि जिला शिक्षा अधिकारी से भी अनुरोध किया गया है कि स्कूलों में बेटी बचाओ के प्रति विद्यार्थियों को प्रार्थना सभाओं में जागरूक करें और समय-समय पर रैली निकाली जाए। एडीसी ने निर्देश दिए कि कम लिंगानुपात वाले गांवों की सूची भी अगली बैठक में प्रस्तुत की जाए और इन गांवों से जुड़े डाक्टर्स व एएनएम को भी बैठक में बुलाया जाए। बैठक में उप सिविल सर्जन डॉ. शशि गर्ग, सीडीपीओ संतोष गिरधर, डीसीओ रितु मेहला भी मौजूद रही।

आढ़ती की मिलीभगत मिलने पर लाइसेंस होगा रद्द: डा. आनंद कुमार शर्मा

टीम एक्शन इंडिया राजकुमार प्रिंस करनाल। उपायुक्त डॉ. आनंद कुमार शर्मा ने जिला की मंडियों में उत्तर प्रदेश से आने वाले गेहूं पर रोक लगाने के लिए सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि यदि ऐसे मामलों में किसी आढ़ती की मिलीभगत पाई जाए तो फौरन उसका लाइसेंस रद्द किया जाए। अन्यथा मंडी सचिव पर भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मंडियों में गेहूं उठाने के कार्य में भी तेजी लाने के निर्देश दिए। उपायुक्त जिला सचिवालय सभागार में जिला के एसडीएम और गेहूं खरीद एजेंसियों के अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कई स्थानों से यूपी से जिला की मंडियों में गेहूं पहुंचने की शिकायतें मिल रही हैं। इसे हर हाल में रोकना होगा। उन्होंने कहा



कि गेहूं की बाहरी आवक में यदि किसी आढ़ती की मिलीभगत पाई जाए तो तुरंत उसका लाइसेंस रद्द किया जाए। ऐसे मामलों में यदि मंडी सचिवों की ढील सामने आई तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त ने खरीद एजेंसियों को गेहूं के उठान कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। असंध और घरौड़ा में साइलों पर मजदूरों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए, ताकि लोड होकर जाने वाले गेहूं को वहां वाहनों से तुरंत उतारा जा सके, ताकि मंडियों

से उठान का कार्य सुचारू रूप से हो सके। उपायुक्त ने निर्देश दिए कि सभी अधिकारी समन्वय के साथ कार्य करें, किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त डॉ. राहुल रईया, डीएफएससी मुकेश कुमार, हैफेड, वेयर हाउस के जिला प्रबंधक, जिला की मार्केट कमेटीयों के सचिवों ने भाग लिया। बैठक में संबंधित एसडीएम वीसी के माध्यम से जुड़े रहे।

कुआं पूजन समारोह बना सामाजिक बदलाव का संदेश

टीम एक्शन इंडिया दिनेश नौताला महेंद्रगढ़। उपमंडल के गांव गढ़ी में डॉ. मनोज गौतम की अगुवाई में उनके भाई संदीप गौतम एवं प्रियंका गौतम की पुत्री चिन्मयी के कुआं पूजन समारोह को सामाजिक सरोकार और पर्यावरण चेतना के साथ मनाया गया। यह आयोजन केवल एक पारिवारिक कार्यक्रम नहीं रहा, बल्कि समाज को नई दिशा देने वाला प्रेरणादायक उदाहरण बनकर उभरा। कार्यक्रम में क्षेत्र के गणमान्य व्यक्तियों, समाजसेवियों, शिक्षाविदों, संत-महात्माओं तथा ग्रामीणों की भारी उपस्थिति रही। आयोजन की इस प्रेरक पहल के बारे में बेटी के ताऊ डॉ. मनोज गौतम ने बताया कि पूरे कार्यक्रम को प्लास्टिक मुक्त रखा गया तथा भोजन में शुद्धता का विशेष ध्यान रखते हुए संधा नमक, शुद्ध घी एवं तेल का प्रयोग किया गया।

नाबालिग से दुष्कर्म का मामला बाल कल्याण समिति की सिफारिश पर जीरो एफआईआर दर्ज

टीम एक्शन इंडिया राजकुमार प्रिंस करनाल। जिले में नाबालिग शोषण का मामला सामने आने के बाद बाल कल्याण समिति की सिफारिश पर पुलिस ने जीरो एफआईआर दर्ज कर दी है। मामले में आरोप है कि हिसार और पानीपत के दो युवकों ने बच्ची को बहला-फुसलाकर उसका शोषण किया। पुलिस ने केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई के लिए हिसार भेज दिया है, जबकि पीड़िता को फिलहाल सुरक्षित आश्रय में रखा गया है। शिकायतकर्ता मां ने बीती 13 अप्रैल को अपनी 16 वर्षीय बेटी को बाल कल्याण समिति करनाल के समक्ष प्रस्तुत किया। मां ने बताया कि बच्ची बार-बार घर से निकल जाती

है। इसके बाद समिति ने बच्ची की कार्डसलिंग करवाई, जिसमें कई चौकाने वाले खुलासे सामने आए। काउंसलिंग के दौरान बेटी ने लिखित में बताया कि उसका बाल विवाह 7 जुलाई 2025 को तय किया गया था। उस समय समिति ने उसे रतनगढ़ से रेस्क्यू कर श्रद्धांदर अनाथालय करनाल में अस्थायी रूप से रखा था। बाद में बच्ची की इच्छा के अनुसार उसे उसकी मां के सुपुर्द कर दिया गया। लेकिन 29 जुलाई 2025 को माता-पिता ने उसे फिर उसी लडके के पास भेज दिया, जिससे उसकी शादी थी थी। बच्ची ने बताया कि हिसार जिला के एक गांव में रहने वाले कुलदीप ने उसके साथ शारीरिक शोषण किया।

49 लाख के सामान से लड़ा ट्रक गायब

टीम एक्शन इंडिया राजकुमार प्रिंस करनाल। नोएडा से जालंधर जा रही एक माल से भरी गाड़ी को ड्राइवर द्वारा रास्ते में ही गायब करने का मामला सामने आया है। घटना करनाल जिले के नीलोखेड़ी पुल के पास की है, जहां ड्राइवर ने कथित रूप से बेईमानी की नीयत से सुपरवाइजर को नीचे उतारकर ट्रक सहित फरार हो गया। फर्म के मालिक की शिकायत मिलने के बाद बुटाना थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जालंधर जिला के गांव शेरपुर शेखे के प्रमिंद सिंह पुत्र सुच्चा सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनकी फर्म प्रमिंद गुड्स कैरियर के नाम से चलती है। उनकी गाड़ी 14 अप्रैल को नोएडा से सामान लेकर जालंधर के लिए रवाना हुई थी। गाड़ी का ड्राइवर गांव संगोजला जिला

कपूरथला निवासी अवतार सिंह पुत्र इन्द्र सिंह था। शिकायत के अनुसार नीलोखेड़ी पुल चढ़ते से पहले ड्राइवर की नीयत बदल गई और उसने कंपनी के सुपरवाइजर विकास सिंह को गाड़ी से नीचे उतार दिया। इसके बाद वह ट्रक और सामान लेकर मौके से फरार हो गया। प्रमिंद सिंह के अनुसार इस घटना में उनका करीब 49 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। उन्होंने पुलिस से ड्राइवर, गाड़ी और सामान की जल्द तलाश करने की मांग की है। मामले की शिकायत मिलने पर बुटाना थाना में मुकदमा 21 अप्रैल को दर्ज किया गया है। जांच अधिकारी के तौर पर एसआई गुरवचन सिंह को मामला सौंपा गया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी ड्राइवर और गाड़ी की तलाश के लिए कार्रवाई जारी है और जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा।

आरोप

आरोप है कि उसने एससी समाज को नीचा दिखाने के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया

टीम एक्शन इंडिया राजकुमार प्रिंस करनाल। जिले के गांव गोंदर में सूरज हत्याकांड को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान एससी समाज पर कथित अभद्र टिप्पणी का मामला अब तूल पकड़ गया है। मंगलवार को बड़ी संख्या में एससी समाज के लोग जिला सचिवालय पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि जब तक केस दर्ज नहीं होता और संबंधित महिला सार्वजनिक माफी नहीं मांगती, तब तक वे सचिवालय के बाहर धरने पर बैठे रहेंगे।



मंगलवार को एससी समाज के लोग एकजुट होकर करनाल के जिला सचिवालय पहुंचे। यहां उन्होंने नारेबाजी करते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि इस तरह की टिप्पणियां पूरे समाज का अपमान हैं और इससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ सकता है। उन्होंने प्रशासन से तुरंत एफआईआर दर्ज करने और दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग की। निरसिंह निवासी जसबीर कुमार ने पुलिस को दी शिकायत

में बताया कि वह अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं। उन्होंने बताया कि बीती 19 अप्रैल को गांव गोंदर में सूरज की हत्या के मामले में कार्रवाई को लेकर उसके परिवार के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने एससी समाज के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की। शिकायत के अनुसार गांव गोंदर के कुलदीप राणा ने भीड़ के बीच एससी समाज को निशाना बनाते हुए कहा कि हमने चूड़ में नहीं पहन रखी, हम भी राजपूत हैं

और पूरे गांव को खाली करवाने का दम रखते हैं। आरोप है कि उसने एससी समाज को नीचा दिखाने के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया और माहौल को भडकाने की कोशिश की। करनाल में एडवोकेट सोनिया तंवर के अनुसार उसी भीड़ में गोंदर निवासी रानी देवी ने भी एससी समाज की महिलाओं को लेकर अभद्र टिप्पणी की। आरोप है कि उसने महिलाओं को निशाना बनाते हुए अपमानजनक और आपत्तिजनक शब्द कहे, जिससे माहौल और अधिक तनावपूर्ण हो गया। शिकायत में कहा कि अजय उर्फ वापू पुत्र उदय सिंह निवासी गोंदर ने भीड़ में एससी समाज के लोगों को गाली देते हुए धमकी दी। आरोप है कि उसने हिंसा भडकाने और गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी। इसके अलावा दो-तीन अन्य लोगों पर भी जान से मारने और मारपीट की धमकी देने का आरोप लगाया गया है।

घरौंडा की अनाज मंडी में लगी आग, गोदामों के बीच गली में डाला था कचरा

टीम एक्शन इंडिया राजकुमार प्रिंस करनाल। जिले के कस्बा घरौंडा की नई अनाज मंडी में दोपहर के समय कचरे में आग लगने से हडकंप मच गया। वेयरहाउस गोदामों के बीच गली में फैले कचरे में लगी आग से पूरी मंडी में धुआं फैल गया। समय रहते आग पर काबू नहीं पाया जाता तो वेयर हाउस के गोदाम तक आग पहुंच सकती थी। कचरा गोदाम की दीवार के नीचे ही डाला हुआ है। इसके अलावा गली के सामने ही आढ़तियों ने गेहूं को तिरपाल से ढक कर रखा हुआ है, जिससे तेज हवा से निगिरी चट्टे तक भी पहुंच सकती थी। घटना के बाद मार्केट कमेटी और सफाई व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। मंगलवार को दोपहर करीब एक



बजे मंडी के वेयरहाउस गोदामों के बीच वाली गली में पड़े मंडी से निकले गेहूं के कचरे में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते गली में धुआं भर गया। गली के दोनों ओर गोदाम थे और सामने गेहूं के चट्टे तिरपाल से ढके हुए रखे थे। ऐसे में आग फैलने का खतरा काफी ज्यादा था। आग लगते ही आढ़तियों और

व्यापारियों के हाथ-पांव फूल गए। मजदूरों ने तुरंत गेहूं के चट्टों के आसपास पानी का इंतजाम किया। मौके पर मौजूद एक व्यापारी ने बताया कि अचानक पूरे इलाके में धुआं फैल गया, जिससे डर का माहौल बन गया। उन्होंने कहा कि अगर आग चट्टों या गोदाम तक पहुंच जाती तो बड़ा नुकसान हो सकता था।

पर फसल अवशेषों में आग लगी हुई है। जहां पर बड़ी गाड़ी भेजी हुई है और मंडी में आग बुझाने के लिए छोटी गाड़ी को बार-बार फायर स्टेशन जाकर पानी भरना पड़ा। इस मामले में मार्केट कमेटी के उप सचिव सुनील कुमार ने बताया कि मंडी के लिए अलग से ड्रॉपिंग यां की व्यवस्था नहीं हो पाई थी। सीजन के चलते कहीं जगह खाली नहीं थी, इसलिए कचरा मंडी में ही डाला जा रहा था। उन्होंने आशंका जताई कि किसी शरारती तत्व ने कचरे में आग लगाई है। उन्होंने कहा कि फायर ब्रिगेड को तुरंत सूचना दी गई थी और आग पर काबू पा लिया गया है। साथ ही आश्वासन दिया कि अब मंडी में कचरा डालना बंद करवाया जाएगा।

उत्तर रेलवे (ई-नीलामी सूचना)			
वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक /यात्री सेवा, उत्तर रेलवे, दिल्ली मंडल, नई दिल्ली द्वारा पार्किंग लॉट्स /साइट्स के आवंटन हेतु ई-नीलामी आईआरएपीएस पोर्टल (http://ireps.gov.in) पर ई-बोली निम्नलिखित प्रकार से आमंत्रित की जाती है-			
ई-कैंटलॉग संख्या	ई-नीलामी की तिथि एवं समय	रेलवे स्टेशन/स्थान/पार्किंग लॉट	
Parking-13-2026	दिनांक 04.05.2026 को 11:00 बजे	पानीपत (कार) (प्रथम प्रवेश), कुरुक्षेत्र (द्वितीय प्रवेश) (साइकिल स्कूटर), रोहतक (द्वितीय प्रवेश), बरेठा, बुढ़लाडा, करनाल (द्वितीय प्रवेश) (साइकिल-स्कूटर-कार), खैकड़ा (परिसंवरण क्षेत्र), थानेसर, सांपला (मुख्य प्रवेश), सांपला (द्वितीय प्रवेश), कुरुक्षेत्र (प्रथम प्रवेश) (साइकिल-स्कूटर-कार) = कुल 11 साइटें।	
वेबसाइट विवरण जहां ई-नीलामी दस्तावेज का पूरा विवरण देखा जा सकता		https://ireps.gov.in/	
आईआरपीएस के माध्यम से आयोजित ई-नीलामी में भाग लेने हेतु निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करना अनिवार्य है:			
1. इच्छुक बोलीदाताओं को आईआरपीएस (वाणिज्यिक नीलामी मॉड्यूल) में ऑनलाइन पंजीकृत करना होगा। पहले से ही अन्य आईआरपीएस खाता रखने वाली संस्थाएं भी खुद को वाणिज्यिक नीलामी मॉड्यूल के लिए नामांकित करने में सक्षम होंगी।			
2. एकमुश्त पंजीकरण शुल्क का भुगतान			
3. भारतीय स्टेट बैंक में चालू खाता			
4. आईआरपीएस खाते के साथ भारतीय स्टेट बैंक के खाते का एकीकरण।			
5. फण्ड का लिधन मार्फित			
6. टर्नओवर का अद्यतनीकरण (updaton)			
7. जिन ठेकेदारों के पास आईआरपीएस के किसी भी मॉड्यूल के लिए आईआरपीएस खाता नहीं है, वे आईआरपीएस होम पेज पर नए विक्रेताओं / ठेकेदारों (ई-निविदा / ई-नीलामी लीजिंग) लिंक पर क्लिक करके पंजीकरण हेतु अपना अनुबंध प्रस्तुत कर सकते हैं।			
सम्बंधित जानकारी हेतु रेलवे प्राधिकारी		वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक /पीएस, डीआरएम कार्यालय, स्टेट एंटी रोड नई दिल्ली 110055 pkg.delhidivision@gmail.com Tel: 011-23743084	
संख्या 23AC/393/E-Auction/PKG/2026 Dated: 21.04.2026			
1316/2026			
ग्राहकों की सेवा में मुख्यालय के साथ			



संपादकीय

आधी आबादी की योगी कैबिनेट में बड़ेगी हिस्सेदारी !

चुनावी साल में उत्तर प्रदेश की सियासत में राजनैतिक हलचल तेज होती जा रही है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों की घड़ी सिर पर आ रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी सरकार की ताकत को मजबूत करने के लिए कैबिनेट विस्तार की तैयारी में जुटे हैं। ख़ास बात यह है कि इस विस्तार का केंद्र बिंदु महिला वोटरों को खुश करना हो सकता है। लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक के गिरने के बाद भाजपा ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे विरोधी दलों पर महिला विरोधी होने का ऐसा तंज कसा है कि पूरा माहौल बन गया है। इसी माहौल का फायदा उठाते हुए योगी सरकार कैबिनेट में महिला मंत्रियों की संख्या बढ़ाकर मतदाताओं का दिल जीतने की कोशिश कर सकती है। न केवल महिलाएं, बल्कि ब्राह्मण, पिछड़ी जाति और दलित वोटरों की भी रिझाने के लिए इन वर्गों को अधिक प्रतिनिधित्व देकर सियासी समीकरण साधे जा सकते हैं। यह कदम चुनावी साल में सत्ताधारी दल की चतुराई का नमूना पेश करेगा। राज्य की राजनीति हमेशा से जाति, धर्म और लिंग आधारित समीकरणों पर टिकी रही है। योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभालते ही हिंदुत्व और विकास के एजेंडे पर जोर दिया, लेकिन अब चुनावी दबाव से सामाजिक समावेश को प्राथमिकता मिल रही है। वर्तमान कैबिनेट में महिलाओं की संख्या सीमित है। बेबी रानी माहौर और स्वाति सिंह जैसी कुछ नेता हैं, लेकिन कुल मिलाकर प्रतिनिधित्व कमजोर पड़ता है। अगर कैबिनेट का विस्तार होता है, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश से आगया की भाजपा सांसद डॉ. प्रेमिला कटियार या गोरखपुर की रवीना कुरेल जैसी सक्रिय महिला नेताओं को जगह मिल सकती है। पश्चिमी इलाके से मेरठ की राजकुमारी दीया या सहारनपुर की उषा सिद्ध भी दावेदार हो सकती हैं। इनमें से कई विधायक या सांसद हैं, जो जमीनी मुद्दों पर मुखर रही हैं। महिला आरक्षण विधेयक को लेकर भाजपा ने जो प्रचार किया, उसके जवाब में यह कदम महिलाओं को संदेश देगा कि हमारी सरकार उन्हें सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। लोकसभा चुनावों के दौरान भाजपा ने महिला आरक्षण बिल को लेकर जो शोर मचाया, वह अब विधानसभा स्तर पर फल दे सकता है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर लगाए गए महिला विरोधी ठप्पे ने विपक्ष को रक्षात्मक बना दिया है। योगी सरकार इसी मौके को भुनाने के लिए कैबिनेट में कम से कम चार-पांच नई महिला मंत्रियों को शामिल कर सकती है। इससे ग्रामीण महिलाओं से लेकर शहरी मतदाताओं तक संदेश जाएगा कि भाजपा महिलाओं के हितों की रक्षा करेगी। उदाहरण के तौर पर, बुनकर बाहुल्य इलाकों से पिछड़ी जाति की महिलाओं को जगह देकर दोहरी रणनीति अपनाई जा सकती है। अवध क्षेत्र की लक्ष्मी चौधरी या बुंदेलखंड की सुनीता सिद्ध जैसी नेता इस फॉर्मूले में फिट बैठती हैं। कैबिनेट विस्तार से न केवल संख्या बढ़ेगी, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों और जातियों का प्रतिनिधित्व भी सुनिश्चित होगा।



संजय सक्सेना

“मुख्यमंत्री ने स्पष्ट संकेत दिया कि इस

आक्रोश को बूथ स्तर तक अभियान के रूप में आगे

बढ़ाया जाएगा। इसका

मतलब यह है कि आने वाले

समय में ब्लॉक, मंडल और

जिला स्तर पर इसी तरह

के कार्यक्रमों की श्रृंखला

देखने को मिल सकती है।

यह रणनीति सीधे तौर पर

संगठनात्मक मजबूती और

जनसंपर्क दोनों को साधने

की दिशा में उठाया गया

कदम मानी जा रही है।

महिला आरक्षण को आधी

आबादी का अधिकार

बनाकर पेश करने की

योजना भी इस अभियान का

महत्वपूर्ण हिस्सा है।

प्रकृति संरक्षण, संतुलन और मानव अस्तित्व का प्रश्न

सुरेश सिंह
यह धरा यह पृथ्वी यह धरती केवल एक ग्रह नहीं, बल्कि जीवन का आधार, अस्तित्व का केंद्र और समस्त जीवों का साझा घर है। 22 अप्रैल को मनाया जाने वाला पृथ्वी दिवस हमें इस मूल सत्य की ओर पुनः ध्यान आकर्षित करता है कि हम प्रकृति से अलग नहीं, बल्कि उसी का अभिन्न हिस्सा हैं। यदि पृथ्वी सुरक्षित है, तो ही मानव सभ्यता का भविष्य सुरक्षित है। पिछले कुछ दशकों में मानव के विकास की अभूतपूर्व ऊँचाइयाँ प्राप्त की हैं। औद्योगिकीकरण, शहरीकरण और तकनीकी प्रगति ने जीवन को सुविधाजनक और तेज बनाया है, लेकिन इस विकास की कीमत भी हमें चुकानी पड़ रही है। जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, वायु और जल दूषण, वन विनाश और जैव विविधता का ह्रास—ये सभी संकेत हैं कि प्रमाण हैं कि संतुलन को गंभीर रूप से प्रभावित किया है।सबसे चिंताजनक बात यह है कि इन समस्याओं का प्रभाव केवल पर्यावरण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सीधे मानव जीवन को प्रभावित कर रहा है। बढ़ता तापमान, अनियमित वर्षा, प्राकृतिक आपदाओं की आवृत्ति में वृद्धि और जल संकट—ये सभी इस बात के प्रमाण हैं कि यदि हमने समय रहते कदम नहीं उठाए, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवन और भी कठिन हो जाएगा। पृथ्वी दिवस हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि विकास

और पर्यावरण के बीच संतुलन कैसे स्थापित किया जाए। यह आवश्यक है कि हम सतत विकासकी अवधारणा को अपनाएँ जहाँ वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य की पीढ़ियों के अधिकारों से समझौता न किया जाए। इस दिशा में छोटे-छोटे कदम भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। जल संरक्षण, ऊर्जा की बचत, प्लास्टिक का कम उपयोग, वृक्षारोपण और पर्यावरण के प्रति जागरूकता—ये सभी ऐसे प्रयास हैं, जिन्हें हर व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में अपना सकता है। जब समाज का हर वर्ग इसमें सहभागी बनेगा, तभी वास्तविक परिवर्तन संभव होगा। सरकारों और नीतियों की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। पर्यावरण संरक्षण के लिए कठोर कानून, स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा, और औद्योगिक गतिविधियों पर नियंत्रण- ये सभी कदम आवश्यक हैं। लेकिन केवल नीतियाँ पर्याप्त नहीं हैं; उनका प्रभावी क्रियान्वयन और जनसहभागिता भी उतनी ही जरूरी है। यह भी समझना होगा कि प्रकृति का दोहन अंततः मानव के लिए ही हानिकारक सिद्ध होता है। हम जिस वायु में सांस लेते हैं, जिस जल को पीते हैं और जिस भूमि पर रहते हैं- यदि वही प्रदूषित हो जाए, तो जीवन की गुणवत्ता स्वतः ही प्रभावित हो जाती है। इसलिए पर्यावरण संरक्षण कोई विकल्प नहीं, बल्कि अनिवार्यता है।



रणनीति अपनाई।लखनऊ में निकली इस पदयात्रा में मुख्यमंत्री के साथ दोनों उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य के अलावा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। सिर पर गमछा बांधे मुख्यमंत्री का पैदल चलना एक प्रतीकात्मक संदेश की तरह देखा गया। इससे यह संकेत देने की कोशिश रही कि सरकार इस मुद्दे को लेकर केवल बयानबाजी तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि इसे जन आंदोलन का स्वरूप देना चाहती है। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो महिला मतदाताओं की बढ़ती संख्या इस पूरे अभियान की सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है। पिछले एक दशक में कई राज्यों के चुनावों में महिला मतदाताओं की भागीदारी पुरुषों के बराबर या कई जगहों पर उससे अधिक रही है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में महिला मतदाताओं की संख्या करोड़ों में है और कई विधानसभा क्षेत्रों में उनकी भूमिका निर्णायक साबित होती रही है। ऐसे में महिला आरक्षण का मुद्दा सीधे तौर पर चुनावी गणित को प्रभावित कर सकता है।पदयात्रा के दौरान नेताओं के भाषणों में विपक्षी दलों पर तीखे हमले देखने को मिले। पंकज चौधरी ने अपने संबोधन में कहा कि कुछ दल वोट बैंक की राजनीति के कारण महिलाओं के अधिकारों के मुद्दे पर पीछे हट गए। उनका कहना था कि राजनीतिक समीकरणों के चलते महिलाओं के अधिकारों की अनेदेखी की गई। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने

विपक्ष को अलोकतांत्रिक बताते हुए कहा कि जो दल महिलाओं के अधिकारों के सवाल पर विरोध करते हैं, वे आधी आबादी के हितों के खिलाफ खड़े दिखाई देते हैं। इस पूरे आयोजन का एक अहम पहलु यह भी रहा कि इसे केवल एक दिन के कार्यक्रम तक सीमित नहीं रखने की बात कही गई। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट संकेत दिया कि इस आक्रोश को बूथ स्तर तक अभियान के रूप में आगे बढ़ाया जाएगा। इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में ब्लॉक, मंडल और जिला स्तर पर इसी तरह के कार्यक्रमों की श्रृंखला देखने को मिल सकती है। यह रणनीति सीधे तौर पर संगठनात्मक मजबूती और जनसंपर्क दोनों को साधने की दिशा में उठाया गया कदम मानी जा रही है।महिला आरक्षण को ह्दआधी आबादी का अधिकारह्द बनाकर पेश करने की योजना भी इस अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। राजनीतिक विक्षेपकों का मानना है कि किसी भी मुद्दे को व्यापक समर्थन दिलाने के लिए उसे भावनात्मक और सामाजिक स्तर पर स्थापित करना जरूरी होता है। महिला आरक्षण के साथ ह्दआधी आबादीह्द का नारा जोड़कर इसे अधिकार और सम्मान के सवाल के रूप में पेश करने की कोशिश दिखाई दे रही है। इस पदयात्रा का एक सामाजिक पक्ष भी है। पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं से जुड़ी योजनाओं को लेकर लगातार प्रचार किया जाता रहा है। उच्चला योजना, शौचालय निर्माण, मातृत्व सहायता और आवास योजनाओं



विचार

किताबों की बेशकीमती ताकत को पहचानो

डॉ. प्रितम भि. गेडाम

1995 से हर साल यूनेस्को 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस मनाता है, 100 से ज्यादा देशों में पढ़ने, प्रकाशन और प्रकाशनाधिकार को बढ़ावा देता है। यह विशेष दिवस हमें पुस्तकों के करीब जाकर उसकी महत्ता को जीवन में उतारने के लक्ष्य को साधने के लिए प्रेरित करता हैं। इस साल 2026 के लिए विश्व पुस्तक दिवस की थीम, अपनी शैलीनुसार पढ़ें यह है, जो पढ़ने के शौक को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करती हैं। यह शैली दशार्ती है कि, जिस प्रकार के भी साहित्य में रूचि हो, वह पढ़ें, पढ़ने की आदत डालें। पुस्तकें जीवन का प्रतिबिंब होती है, सच और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए पुस्तकें प्रेरित करती हैं। दुनिया भर के महानतम व्यक्ति अपनी खास उपलब्धि के लिए प्रसिद्ध हुए। पैसा, शोहरत, नाम, काम और वस्तुता के बावजूद और हर मिनट के लाखों रुपये कमानेवाले उद्योगपति, खेल जगत के खिलाडी, नेता और फिल्मी नायक भी पुस्तकें पढ़ने के लिए रोजाना अपना कीमती समय थोड़ा ही सही लेकिन निकालते जरूर हैं। क्या हम कभी पुस्तकें खरीदने के लिए आर्थिक समस्या से जूझने पर अपना एक वक्त का भोजन छोड़कर उससे पैसे बचाकर पुस्तकें खरीदने की कोशिश की हैं। विश्व में ज्ञान का प्रतिक कहलानेवाले भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ने अपने तंगी के दिनों में पुस्तकें खरीदने के लिए एक वक्त का भोजन तक

त्याग दिया था, ताकि ज्ञानरूपी पुस्तकों का तेज आत्मसात कर सकें, ये होता है किताब के प्रति जुनून और किताब की महत्ता की समझ। अधिकतर बड़े-बड़े लोग अक्सर अपने घर में ही पुस्तकों का संग्रह बना लेते है, अर्थात निजी पुस्तकालय के तौर पर। पुस्तकों से बेहतर दुनिया में कोई साथी नहीं होता, पुस्तकें हमेशा हमें योग्य दिशा में चलने के लिए पथ प्रदर्शित करते है, पुस्तकें हमारे खाली समय को ज्ञान से सींचते है, बुद्धि को तिण्ण, जागरूक, समझदार बनाकर सत्य और असत्य के बिच अंतर करना सिखाते हैं। हम पुस्तकों और शिक्षा के बल पर दुनियाभर में हर क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर सकते हैं। विश्व पुस्तक दिवस पढ़ने, किताबें, प्रकाशन, लेखक पुस्तकें प्रेरित करती हैं। दुनिया भर के महानतम व्यक्ति अपनी खास उपलब्धि के लिए प्रसिद्ध हुए। पैसा, शोहरत, नाम, काम और वस्तुता के बावजूद और हर मिनट के लाखों रुपये कमानेवाले उद्योगपति, खेल जगत के खिलाडी, नेता और फिल्मी नायक भी पुस्तकें पढ़ने के लिए रोजाना अपना कीमती समय थोड़ा ही सही लेकिन निकालते जरूर हैं। क्या हम कभी पुस्तकें खरीदने के लिए आर्थिक समस्या से जूझने पर अपना एक वक्त का भोजन छोड़कर उससे पैसे बचाकर पुस्तकें खरीदने की कोशिश की हैं। विश्व में ज्ञान का प्रतिक कहलानेवाले भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ने अपने तंगी के दिनों में पुस्तकें खरीदने के लिए एक वक्त का भोजन तक

और संवाद कौशल बेहतर बनाती है, संस्कृति और इतिहास का जतन करके अलग-अलग पीढ़ियों के पाठकों को आपस में जोड़ती है, साथ ही शिक्षा और ज़िंदगी भर सीखने में मदद करती हैं। नियमित पाठन से शब्दसंग्रह, एकाग्रता, आत्मविश्वास और विचारशक्ती कौशल बेहतर होती हैं। आज विश्व किताब दिवस किताबों की खुशी और ताकत का जश्न मनाने का एक शानदार मौका हैं। पसंदीदा एक नई किताब पढ़कर, पुस्तकालयों को भेंट देकर, दोस्तों रिश्तेदारों या परिचितों से किताबों का आदान-प्रदान करके अथवा किसी में पढ़ने की ललक जगाकर यह दिन मनाया जाना चाहिए। अपनी पसंदीदा पुस्तकों के बारे में अन्य लोगों या मित्रों से विचार-विमर्श करना चाहिए, हमें यह पुस्तक क्यों पसंद है एवं अन्य पाठकों को भी यह पुस्तक क्यों पढ़नी चाहिए। इसका स्पष्टीकरण देना चाहिए, ताकि अन्य लोग भी प्रेरित होकर वह पुस्तक पढ़ने के लिए उत्सुक हों। अच्छी किताबों की हमेशा प्रोत्साहन मिलना चाहिए, ताकि योग्य किताबें पाठकों तक आसानी से पहुंच सकें, जो मनुष्य किताबों से दोस्ती करता है, उसे सफलता के मार्ग पर अग्रसर होने से कभी कोई रोक नहीं सकता, किताबों में समस्या का समाधान छुपा होता है। किताबें कभी कोई शिक्षायात्र नहीं करती, वें बस निरंतर ज्ञान की गंगा बहाते चलती हैं। जिसने उसे अपनाया जो सफल गया, जिसने किताबों की महत्ता नहीं समझी वो पिछड़ गया।

ग्राम स्वराज, सहभागिता और लोकतंत्र की जड़ें

सुरेश

भारत की आत्मा उसके गाँवों में बसती है— यहाँ केवल एक कथन नहीं, बल्कि हमारे लोकतांत्रिक ढाँचे की आधारशिला है। 24 अप्रैल को मनाया जाने वाला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस हमें उस प्रणाली की याद दिलाता है, जो लोकतंत्र को जमीनी स्तर तक पहुँचाती है और आम नागरिक को शासन का सक्रिय भागीदार बनाती है। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य ग्राम स्वराज की अवधारणा को साकार करना है—एक ऐसा तंत्र, जिसमें गाँव स्वयं अपने विकास, संसाधनों और निर्णयों के लिए सक्षम और स्वायत्त हो। महात्मा गांधी ने जिस स्वराज की कल्पना की थी, उसकी वास्तविक अभिव्यक्ति पंचायतों के माध्यम से ही संभव है। यह व्यवस्था न केवल प्रशासनिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देती है, बल्कि लोकतंत्र को जन-जन तक पहुँचाने का कार्य भी करती है। भारत में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा 73वें संविधान संशोधन (1992) के माध्यम से मिला, जिसने इसे एक सशक्त और व्यवस्थित ढाँचा प्रदान किया। इसके तहत ग्राम

पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद—तीन स्तरों पर प्रशासनिक संरचना स्थापित की गई। यह प्रणाली स्थानीय आवश्यकताओं को समझते हुए योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने में सक्षम बनाती है। पंचायतें केवल विकास योजनाओं के क्रियान्वयन का माध्यम नहीं हैं, बल्कि वे सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की भी आधारशिला हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था ने इन वर्गों को निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी का अवसर प्रदान किया है। विशेष रूप से महिलाओं की भागीदारी ने ग्रामीण प्रशासन में एक नई संवेदनशीलता और दृष्टिकोण को जन्म दिया है। हालाँकि, इस व्यवस्था के सामने कई चुनौतियाँ भी हैं। कई स्थानों पर संसाधनों की कमी, प्रशासनिक अनुभव का अभाव, और कभी-कभी राजनीतिक हस्तक्षेप पंचायतों की कार्यक्षमता को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा, पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी भी एक महत्वपूर्ण समस्या है, जिसे दूर करने की आवश्यकता है।



आलेख

पृथ्वी दिवस पर इस ग्रह की देखभाल करें और आध्यात्मिक रूप से विकसित हों

- **संत राजिन्दर सिंह जी महाराज**

पृथ्वी दिवस हम सबके लिए पृथ्वी के प्रति आधार व्यक्त करने का दिन है क्योंकि यह हमें जीवन जीने के लिए कई प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों को उपलब्ध करती है। यह सभी संसाधन न सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी मूल्यवान है, इसलिए हम सभी को चाहिए कि इन संकेत—ये सभी इस बात के प्रमाण हैं कि यदि हमने समय रहते कदम नहीं उठाए, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवन और भी कठिन हो जाएगा। पृथ्वी दिवस हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि विकास

हमें खुशी मिलती है कि इस विषाल अंतरिक्ष में यह ग्रह पिता-परमेश्वर का बनाया एक खूबसूरत रत्न है, जिसमें हम सब इस परिवार के एक सदस्य हैं। इसलिए हमें ऐसे कार्य करने चाहियें जिसमें कि हम एक-दूसरे की मदद करते हुए प्रेम और शांतिपूर्वक जी सकें। इस ग्रह पर रहते हुए हम स्वस्थ तरीके से अपना जीवन यापन करें, ताकि हमारे परिवार और पूरे विश्व के लिए वर्तमान में और आने वाले समय में भी पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हों। इसके लिए हमें चाहिये कि हम इस ग्रह की देखभाल करते हुए शारीरिक, मानसिक और आत्मिक तौर पर विकसित हों। जिसके लिए हमें एक शाकाहारी जीवन शैली को अपनाना होगा और साथ ही साथ अपनी आत्मिक तत्कवी के लिए अपने जीवन

में हमें सदुणों को भी धारण करना होगा। जिसमें कि हम दूसरों की सेवा करते हुए ध्यान-अभ्यास के जरिये अपने अंतर में प्रभु-सत्ता से जुड़कर आध्यात्मिक रूप से विकसित हो सकते हैं। दूसरों की सेवा करना और मिल-जुलकर रहना आध्यात्मिकता का ही एक हिस्सा है। दूसरों के साथ मिलकर रहना और इस पृथ्वी की रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है क्योंकि इस सृष्टि के कण-कण में परमात्मा विद्यमान हैं। आइये, आध्यात्मिक रूप से बढ़ते हुए हम इस ग्रह, पेड़-पौधों, जानवरों और इंसानों की देखभाल करते हुए हम पृथ्वी दिवस मनायें और पृथ्वी द्वारा दिये गए बहुमूल्य उपहारों का सर्वोत्तम उपयोग करें।

एक्शन इंडिया दैनिक

भगवान शंकर जी के ग्यारहवें रुद्रावतार हनुमान जी (मेहदीपुर, श्री बाला जी) के संरक्षण में संचालित किया जाता है। समाचार-पत्र का यह अंक भी उन्हीं के चरणों में श्रद्धापूर्वक समर्पित है।

आरएनआई: DELHIN / 2006 / 19302

एक्शन इंडिया मट्रीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड के लिए संपादक, मुद्रक, प्रकाशक एवं रवि भारद्वाज द्वारा एक्शन बालाजी हाउस, 244, ब्लॉक- बी, तैमन- 3, राकेश भारद्वाज चौक के नजदीक, दिल्ली – 110033 से प्रकाशित एवं मासुतिनंदन प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स, शक्ति कॉम्प्लेक्स, 6/18, समयपुर इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली-110042 से मुद्रित।

संस्थापक : श्रेष्ठेय शक्ति भारद्वाज जी
समूह संपादक : रवि भारद्वाज (9999889104)
मेट्रो संपादक : दीपचंद कांडपाल (8447314925)
‘एक्शन इंडिया’ में प्रकाशित लेखों में व्यक्त किये गए विचार एवं दृष्टिकोण संबंधित लेखक के हैं। संपादक केवल वीआरवी एक्ट के तहत ही उत्तरदायी। किसी भी विवाद का न्यायिक क्षेत्र दिल्ली ही होगा।

वैधानिक सूचना

पाठकों को सलाह है कि एक्शन इंडिया, समाचार पत्र में प्रकाशित किसी भी विज्ञापन के आधार पर कोई निर्णय लेने से पहले विज्ञापन में प्रकाशित उक्त उत्पाद या सेवा से न आवश्यक जीव-पड़ताल कर लें। समाचार पत्र प्रबंधक किसी भी विज्ञापन में गुणवत्ता, बराे आदि के विवरण के बारे में विज्ञापनदाता द्वारा किए गए दावे या उल्लेख की पुष्टि या समर्थन नहीं करता है। अतः समाचार पत्र उक्त विज्ञापनों के बारे में किसी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

न्यूज प्लैश

दुकानों का बकाया किराया जमा न करवाने वाले किराएदारों की चल व अचल सम्पतियां होंगी अटैच, निगम करेगा कार्रवाई : डॉ. वैशाली शर्मा

टीम एक्शन इंडिया कमल मिश्र



नगर निगम की दुकानों का किराया जमा न करवाने वाले किराएदारों के विरुद्ध निगम अब सख्ती से निपटेगा। इसके तहत सील की गई दुकानों का बकाया जमा न करवाने वाले किराएदारों की चल व अचल सम्पतियों को नगर निगम अटैच करेगा। इसे लेकर निगम के प्रवर्तन दल ने अपनी तैयारी पूरी कर ली गई है।

नगर निगम आयुक्त डॉ. वैशाली शर्मा ने जानकारी देते बताया कि बीते वित्त वर्ष में सील की गई 18 दुकानों के किराएदारों द्वारा अभी तक बकाया किराए का भुगतान नहीं किया गया है। यह राशि 91 लाख 24 हजार 974 रुपये है। इन दुकानों के सम्बंधित किराएदारों को 3 दिन की मोहलत दी गई है। अगर वह इस अवधि में बकाया किराए का भुगतान नहीं करते, तो सम्बंधित किराएदार की चल व अचल सम्पत्ति को अटैचमेंट करने की कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने बताया कि बड़े बकायादारों की सूची में 133 किराएदारों के नाम हैं, इनमें से उपरोक्त 18 दुकानों को नगर निगम द्वारा सील कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त शेष 115 दुकानों पर भी 36 लाख 9 हजार 691 रुपये का बकाया है। इन किराएदारों को भी किराया जमा करवाने के लिए 3 दिन का समय दिया गया है। इसके पश्चात नगर निगम अपनी कार्रवाई शुरू करेगा।

इन क्षेत्रों की दुकानें हैं शामिल- महर्षि वाल्मिकी चौक, नावल्टी रोड, प्रेम नगर, राम नगर, मीनार रोड, पुराना बस स्टैंड रोड, पुराना पोस्ट ऑफिस, मेरठ रोड, बांसो गेट, अर्जुन गेट, नेहरू पैलेस मार्केट, रणधीर रोड, डॉ. ज्ञान भूषण मार्केट रोड, कर्ण पार्क, कर्ण ताल, कम्बोपुरा, उचानी व उचाना की दुकानें शामिल हैं। वित्त वर्ष 2025-26 में हुई रिकवरी- उन्होंने बताया कि नगर निगम द्वारा वित्त वर्ष 2025-26 में दुकानों के किराए की रिकॉर्ड वसूली की गई है। इस दौरान 1 करोड़ 93 लाख 3 हजार 383 रुपये का राजस्व एकत्रित किया गया है। इसमें किया व बकाया राशि दोनों शामिल हैं। इसके अतिरिक्त ब्याज के रूप में 33 लाख 67 हजार 400 रुपये वसूल किए गए हैं।

विदेश से जानकार बनकर 23 लाख रुपए की ठगी करने के मामले में आरोपी काबू, 5 आरोपी पहले गिरफ्तार

प्रमोद भार्गव,

गुहला चीका। साइबर ठगो पर एसपी मनप्रती सिंह सूदन के आदेशानुसार शिकंजा कसा जा रहा है। ऐसे ही एक मामले में ठगों द्वारा चीका क्षेत्र के एक बुजुर्ग से विदेश से रिश्तेदार बनकर 23 लाख रुपए की ठगी करने के मामले की जांच साइबर क्राइम थाना प्रभारी एसआई रणदीप सिंह की अगुवाई में एसएसआई प्रदीप कुमार की टीम द्वारा करते हुए जरारा पिपरी यूपी हाल नोएडा निवासी साकिब मोहम्मद को काबू कर लिया गया। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि चीका के वार्ड नं. 16 निवासी संतोख की प्रभावित अनुसार उसके दो बेटे 15 साल से इटली गए हुए हैं तथा उसके साले गांव कसौर निवासी बहादुर के भी दो बेटे बलराज व मनजीत भी इटली गए हुए हैं। मनजीत बचपन से ही उनके घर रहता था, इसलिए वह उससे बेटों की तरह प्यार करता था। शिकायतकर्ता अनुसार 29 मई 2023 को उसके पास विदेशी नंबर से कॉल आई। काल करने वाले ने कहा कि फुफंड मै मनजीत बोल रहा हूं, जो वह आरोपी की बातों में आ गया और भावना में बहकर उसने अपनी पत्नी से भी आरोपी की बात करवाई। आरोपी ने उससे कहा कि वह 15 दिन बाद भारत आ रहा है और उसने इटली के डॉकर्स से कागजात बनवाए हैं, जिनके 3 लाख रुपए बनते हैं, जो अभी देने हैं। आप 3 लाख रुपए अभी भेज दो। जो उसने आरोपी को मनजीत समझकर 15 हजार रुपए बताए गए बैंक खाता में जमा करवा दिए। इसके बाद दूसरे युवक की कॉल आई और कहने लगा कि उसने मनजीत के कागजात तैयार करवाए हैं। उसकी मां बीमार है और उसे रुपयों की सख्त जरूरत है। इसलिए आप और रुपए भेजो। इसके बाद उसने 2 लाख 85 हजार रुपए और जमा करवा दिए। इसके बाद दोबारा कॉल आने पर और मां ज्यादा बीमार होने के नाम पर उसने एक लाख रुपए और जमा करवा दिए।

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया हांसी अनाज मंडी का दौरा

टीम एक्शन इंडिया

हांसी (दिनकर गावड़ी):झारूपूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार प्रदेशभर की अनाज मंडियों का दौरा कर रहे हैं।

मंगलवार को उन्होंने हांसी की मंडी का दौरा किया और किसानों, मजदूर व आड़तियों से बातचीत की। उनकी समस्याओं को सुनने के साथ-साथ हुड्डा ने अधिकारियों से भी बातचीत की औ उन्हें व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए।

पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए हुड्डा ने आंकड़ों के साथ बीजेपी को आईना दिखाया।



उन्होंने बताया कि 2013 में कांग्रेस सरकार ने 87 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा की गेहूं की खरीद करी थी। लेकिन जब से भाजपा सत्ता में आई है, सरकारी खरीद का आंकड़ा लगातार घटता गया। इस बार भी सरकार ने मात्र 72 लाख मैट्रिक टन खरीद का

टीम एक्शन इंडिया

कमल मिश्र

करनाल। उपायुक्त डॉ.आनंद कुमार शर्मा ने 26 अप्रैल को करनाल में आयोजित होने वाली एचसीएस परीक्षा के संदर्भ में अधिकारियों की बैठक ली और ड्यूटी मजिस्ट्रेट, फ्लाईंग स्ववायड और सेंटर सुपरिटेण्डेंट को आवश्यक दिशा.निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस परीक्षा को सफलतापूर्वक एवं शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित करवाना हम सबकी ज्यादा जिम्मेदारी है, लापरवाही ना बरतें। उपायुक्त मंगलवार को कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज के सभागार में एचसीएस परीक्षा को लेकर जिला अधिकारियों की बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि हरियाणा सिविल सर्विसेज परीक्षा प्रदेश की प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक है। इसे हरियाणा लोक सेवा आयोग आयोजित कर रहा है। इस परीक्षा के लिए करनाल में 48 सेंटर बनाए गए हैं। इन परीक्षा केंद्रों पर

जियो टावर से 5 आरआरएच चोरी

गन्ौर। गन्ौर-सोनीपत रोड स्थित राजलू गढ़ी में लगे जियो टावर से उपकरण चोरी होने का मामला सामने आया है। पानीपत निवासी पवन कुमार ने थाना बड़ी में दी शिकायत में बताया कि वह एसजी एनकान प्राइवेट लिमिटेड में एस्टेट मैनेजर हरियाणा के पद पर कार्यरत है, जो रिलायंस जियो के नेटवर्क की देखरेख करती है। 28 मार्च को रात अज्ञात चोर 5 टावर रिमोट कंट्रोल हेड चोरी कर ले गए। कंपनी अधिकारियों ने अपने स्तर पर चोरों की काफी तलाश की, लेकिन उनका कोई सुराज नहीं लग सका। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ चोरी का केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

टीम एक्शन इंडिया

गुहला चीका।

हरियाणा सरस्वती हरिटेज बोर्ड के उप-चेयरमैन धुम्मन सिंह किरमच ने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मार्गदर्शन में सरस्वती नदी को जीवित रखने के लिए अनेक विकास कार्य किए जा रहे हैं। हरियाणा में जहां-जहां से सरस्वती नदी गुजरती है वहां पर बने मंदिरों, घाटों के सौंदर्यकरण का कार्य किया जा रहा है। इन विकास कार्यों का मुख्य उद्देश्य आमजन को धार्मिक बढ़ावा देने के साथ-साथ सुविधाएं प्रदान करना है।

ही टारगेट रखा है, जोकि कुल उत्पादन से बहुत काम है। अगर पैदावार और रकबे की बात करें तो आज भी 2013 वाली ही स्थिति है। लेकिन अगर सरकारी खरीद की बात करें तो उसमें भारी गिरावट हो चुकी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि वो लगातार प्रदेशभर की मंडियों का दौरा कर रहे हैं। हालात यह है कि किसानों को भुगतान में 5 से 8 दिन तक की देरी हो रही है। अभी तक किसानों को 2714 करोड़ में से सिर्फ 741 करोड़ का भुगतान हुआ है। यानी लगभग 1972 करोड़ की पेमेंट अभी भी बकाया है।

बैठक

परीक्षा की तैयारियों को लेकर की समीक्षा, 48 सेंटों पर 14616 कैंडिडेट देंगे परीक्षा

सुबह 10 बजे से 12 बजे और 3 बजे से 5 बजे की दो शिफ्ट में परीक्षा होगी। उन्होंने बताया कि परीक्षा केंद्रों पर सुबह 8.30 बजे से 9.50 बजे तक कैंडिडेट एंट्री कर सकते हैं जबकि दूसरी शिफ्ट में 1.30 बजे से 2.50 बजे तक एंट्री होगी। उन्होंने कहा कि परीक्षा को पारदर्शी तरीके से आयोजित करवाना हम सभी का अहम लक्ष्य है। सभी अधिकारियों को पूरी निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य का वहन करना है, कोई लापरवाही न बरतें। परीक्षा के नोडल अधिकारी अतिरिक्त उपायुक्त डॉ. राहुल रईया को बनाया गया है।

जगारुकता

वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय फरीदपुर में विद्यार्थियों के लिए जागरुकता शिविर का आयोजन

टीम एक्शन इंडिया

राजकुमार प्रिंस

करनाला। जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष अजय कुमार शारदा के मार्गदर्शन में मंगलवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा शिक्षा विभाग के सौजन्य से पृथ्वी दिवस के उपलक्ष्य में राजकीय वरिष्ठ



हरियाणा सरस्वती हरिटेज बोर्ड के उप-चेयरमैन धुम्मन सिंह किरमच मंगलवार को हरियाणा-पंजाब बोर्ड पर स्थित गुहला के गांव पिसेली में प्राचीन मां सरस्वती मंदिर परिसर में लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्ष

संदिग्ध परिस्थितियों में महिला लापता

टीम एक्शन इंडिया

गन्ौर। थाना बड़ी क्षेत्र के एक गांव से एक महिला संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। पीड़ित पति ने मामले की शिकायत थाना बड़ी में दी। शिकायत में पीड़ित पति ने बताया जत उसकी पत्नी 20 अप्रैल को दोपहर घर से बिना बताए चली गई और वापस नहीं लौटी। अपने स्तर पर काफी तलाश के बावजूद उसका कोई सुराग नहीं लग सका। पीड़ित ने आशंका जताई कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसकी पत्नी को गुप्त स्थान पर छुपा रखा है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।



उपायुक्त ने कहा कि अधिकारी हरियाणा लोक सेवा आयोग की ओर से एचसीएस की परीक्षा को लेकर जारी दिशा-निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और उनकी अनुपालना सुनिश्चित की जाए। उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए कि जिला में स्थापित परीक्षा केंद्रों की स्थिति और सुविधाओं से संबंधित रिपोर्ट देंगे। इसके अलावा सभी ड्यूटी मजिस्ट्रेट व सुपरवाइजर भी संबंधित परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण करके प्रबंधों का जायजा लें। उन्होंने अतिरिक्त आयुक्त नगर

निगम को निर्देश दिए कि वे करनाल शहर में स्थापित धर्मशालाओं व सामुदायिक केंद्रों में साफ सफाई, शौचालय, बिजली तथा पीने के पानी की समुचित व्यवस्था देखें ताकि दूसरे जिलों से एचसीएस की परीक्षा देने के लिए आने वाले परीक्षार्थियों की ठहरने की व्यवस्था करवाई जा सके। उन्होंने नगराधीश को निर्देश दिए कि वे परीक्षा को लेकर एक कंट्रोल रूम भी स्थापित करवाएं। उन्होंने कहा कि परीक्षा की दृष्टिगत पुलिस विभाग के जिन अधिकारियों व कर्मचारियों की

ड्यूटी लगी है, उनकी सूची ड्यूटी मजिस्ट्रेट, सुपरवाइजर व सेंटर सुपरिटेण्डेंट के साथ साझा की जाए।

इसके अलावा परीक्षा के दिन ट्रैफिक व्यवस्था को भी सुचारू रूप से रखा जाए, ताकि ट्रैफिक जाम की वजह से कोई भी बच्चा परीक्षा देने से वंचित न रहे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ट्रेजरी से लेकर परीक्षा केंद्र तक पेपरों को लेकर ऐसा नजर आया तो संबंधित के खिलाफ तुरंत प्रभाव से एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। उन्होंने जीएम रोडवेज को भी निर्देश दिए कि वे दूसरे जिलों में परीक्षा देने के लिए जाने वाले

जिला के परीक्षार्थियों के लिए भी पर्याप्त मात्रा में बस की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए और उन्हें समय पर रवाना करवाएं। इसके अलावा लोकल स्तर पर भी परीक्षार्थियों के लिए बसों की व्यवस्था रखें। परीक्षा केंद्र के सभी कमरों में लगी हो घड़ी : एडीसी एडीसी डॉ. राहुल रईया ने कहा कि अधिकारी सुनिश्चित करें कि परीक्षा केंद्र के सभी कमरों में घड़ी लगी हो और सभी घड़िों का समय एक हो। परीक्षा केंद्र पर लगे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को भी आई कार्ड दिया जाए। इसके अतिरिक्त परीक्षा केंद्र पर किसी को भी मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा निरीक्षक भी अपना मोबाइल फोन सेंटर सुपरिटेण्डेंट के पास जमा करवाएंगे। इस मौके पर नगराधीश मोनिका शर्मा व जिला शिक्षा अधिकारी रोहताश वर्मा सहित परीक्षा से संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

निवेश के नाम पर लाखों की साइबर ठगी के मामले में आरोपी काबू

टीम एक्शन इंडिया

राजकुमार प्रिंस

करनाला। जिला पुलिस के थाना साइबर अपराध करनाल ने ऑनलाइन निवेश-बिडिंग के नाम पर की गई बड़ी साइबर ठगी के मामले में एक आरोपी को सहायक उप निरीक्षक देवेन्द्र कुमार की गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान धनंजय कुमार पुत्र सुरेश कुमार निवासी वार्ड नंबर 3, टूमंडिया टोला, मोतियारी (बिहार) के रूप में हुई है। मामले की जानकारी देते हुए अनुसंधान अधिकारी ने बताया कि शिकायतकर्ता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसे व्हाट्सएप के माध्यम से वर्क फ्रॉम होम का लालच देकर एक टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ा गया। शुरूआत में छोटे-छोटे टास्क देकर मुनाफा दिखाया गया, जिससे उसका विश्वास जीत लिया गया। इसके बाद अलग-अलग टास्क और निवेश के नाम पर उससे लगातार बड़ी रकम जमा करवाई गई। शिकायतकर्ता ने अपने तथा अपने परिजनों के बैंक खातों से विभिन्न माध्यमों के जरिए लाखों रुपए की राशि आरोपियों द्वारा बताए गए खातों में ट्रांसफर कर दी। बाद में जब और अधिक पैसे की मांग की गई तथा पैसा वापस नहीं मिला, तब उसे ठगी का एहसास हुआ।

पृथ्वी दिवस पर जागरुकता शिविर आयोजित



माध्यमिक विद्यालय फरीदपुर में विद्यार्थियों के लिए जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया। जागरुकता शिविर में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव डॉ. इरम हसन का खूब शिक्षा अधिकारी वीना, लीगल लिटरेसी सेल के नोडल ऑफिसर दिनेश व

सुषमा ने विद्यालय के समस्त स्टाफ के साथ उनका स्वागत किया। कार्यक्रम का शुभारम्भ सीजेएम ने पौधारोपण कर किया। सीजेएम ने लोगों को पर्यावरण सुरक्षा के लिए पौधारोपण में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के दौरान सीजेएम डॉ. इरम हसन ने बताया कि 22

पर थी। पिछले 10 वर्षों के अथक प्रयासों से आज सरस्वती नदी में 400 किलोमीटर में पानी बह रहा है। सरस्वती हरिटेज बोर्ड का मकसद सरस्वती नदी का उत्थान और पुनर्जीवित करना है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी सरस्वती नदी को लेकर समय-समय पर फीडबैक लेते रहते हैं और इन स्थानों के विकास के लिए करोड़ों रुपए के बजट को आर्बिटिट करते हैं। यह मां सरस्वती मंदिर गुहला हलंके का एक ऐतिहासिक स्थान है। इस स्थान पर सरस्वती नदी बहती रही

है, पुराने समय में यहां पर लोग अपने परिजनों के अंतिम संस्कार करने के बाद उनके पिंड दान करने आते थे। लोगों की आस्था और सुविधा को देखते हुए इस पद्धति को दोबारा विकसित किया जाएगा। लोगों की इस मंदिर के प्रति काफी आस्था है। इस क्षेत्र में बड़े-बड़े ऋषि मुनियों ने तपस्या की थी, जिनकी वजह से यह क्षेत्र पावन बना है। उन्होंने कहा कि प्राचीन काल में महाभारत के समय बलराम ने युद्ध में शामिल न होकर उन्होंने द्वारका से लेकर आदिबंदी तक सरस्वती की यात्रा की थी।

6 दिवसीय विशेष योग शिविरों का किया जा रहा आयोजन

टीम एक्शन इंडिया

राजकुमार प्रिंस

करनाल। जिला आयुर्वेद अधिकारी डॉ. सतपाल ने बताया कि हरियाणा योग आयोग के निर्देशानुसार अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस-2026 के उपलक्ष्य में 6 दिवसीय विशेष योग शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि शिविर के दूसरे दिन दिव्यांगजनों के लिए विशेष सत्र समाज कल्याण संस्थान माता प्रकाश कौर वाणी एवं श्रवण निश्कत जन कल्याण केन्द्र में सुबह 6.30 बजे से सत्र आयोजित किया गया। यहां रीटा और सोनू पाल ने विशेष सांकेतिक और सरल विधियों से दिव्यांगजनों को योग का अभ्यास कराया।



इसके बाद वरिष्ठ नागरिकों के लिए सेक्टर-6 स्थित सीनियर सिटीजन डे केयर सेंटर में सुबह 11 बजे से विशेष सत्र आयोजित किया गया।

डॉ.अमित पुंज और कुसुम लता ने

बुजुर्गों को जोड़ों के दर्द और मानसिक तनाव को कम करने वाले सूक्ष्म व्यायाम के बारे में जानकारी दी। जिला नागरिक अस्पताल में गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सत्र आयोजित किया

गुहला में झ्रइविंग लाइसेंस पर सख्ती, 35 से ज्यादा लोगों की मेडिकल जांच: डा. चावला

टीम एक्शन इंडिया

प्रमोद भार्गव,

गुहला चीका।

झ्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। इसी कड़ी में कैथल से आई एक मेडिकल टीम ने मंगलवार को एसडीएम कार्यालय में विशेष जांच अभियान चलाया, जिसमें 35 से अधिक आवेदकों की मेडिकल जांच की गई। मेडिकल टीम के डाक्टर जी.एल. चावला ने जानकारी देते हुए बताया कि हर मंगलवार को एसडीएम कार्यालय गुहला में झ्राइविंग लाइसेंस के लिए मेडिकल

जांच की जाती है। हालांकि, कई बार यह सामने आया है कि कुछ शरारती तत्व या शारीरिक रूप से अनफिट व्यक्ति भी गलत तरीके से लाइसेंस बनवाने में सफल हो जाते हैं। इस पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने सख्त रख अपनाया है। अभियान के दौरान प्रत्येक आवेदक की गहन जांच की गई और केवल उन्हीं लोगों को मेडिकल फिटनेस सर्टीफिकेट जारी किया गया, जो सभी मानकों पर खरे उतरे। डॉक्टर जी.एल. चावला ने बताया कि भविष्य में भी इसी तरह सख्ती बरती जाएगी, ताकि कोई भी अयोग्य व्यक्ति झ्राइविंग लाइसेंस का गलत फायदा न उठा

सके। इसी दौरान रेडक्रास कैथल के प्रवक्ता राम मेहर काजल ने जिला उपायुक्त के आदेशानुसार 35 लोगों को झ्राइविंग लाइसेंस प्रक्रिया के तहत फर्स्ट ऐंड ट्रेनिंग भी प्रदान की। उन्होंने बताया कि सड़क सुरक्षा के लिए फर्स्ट ऐंड ज्ञानकारी की स्थिति जरूरी है, ताकि दुर्घटना की बिल्कुल में तुरंत सहायता दी जा सके। प्रशासन के इस कदम को सड़क सुरक्षा की दिशा में अहम माना जा रहा है। स्थानीय लोगों ने भी इस पहल का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई है कि इससे सड़क हादसों में कमी आएगी और लाइसेंस प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी।

न्यूज प्लैश

शिव योद्धा ने केयूके वॉरियर्स को 30 रन से हराया

टीम एक्शन इंडिया
दलबीर सिंह मलिक
कुरुक्षेत्र: कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के केयू सीनियर सेकेंडरी मॉडल स्कूल के प्रांगण में रविवार को दोपहर बाद खेले गए केयू गैर-शिक्षक कर्मचारी के 5वें टी-20 प्रतियोगिता के अनीपवारिक लीग मैच में शिव योद्धा ने केयूके वॉरियर्स को 30 रन से हराया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी शिव योद्धा की टीम ने 20 ओवर में 173 रन बनाए। ओपनर बल्लेबाज पवन शर्मा ने धुआंधार बैटिंग करते हुए 59 गेंदों में 73 रन बनाए जिसमें उन्होंने 11 चौके व 1 छक्का लगाया। वहीं आदित्य स्वामी ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 14 गेंदों में 9 चौके लगाकर 40 रन बनाए। रवि चौहान ने 3 चौके व 1 छक्के के साथ 30 रन की अहम पारी खेली। केयू वॉरियर्स की ओर से कप्तान दीपक कुमार ने 3 विकेट झटके। विपक्षी टीम केयूके वॉरियर्स निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 143 रन ही बना सकी। मैच में अनिल ख्योंग ने 31 रन बनाए जिसमें 4 चौके व 1 छक्का शामिल रहा। शिव योद्धा की ओर से सूरज जिंदल ने 3, सुमित मेहता ने 2, अरविन्द श्रीवास्तव, गोपाल व आदित्य स्वामी ने 1-1 विकेट लिया। सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजी की बदौलत पवन शर्मा को मैन ऑफ द मैच का खिताब मिला। मैच में अम्पायर की भूमिका सागर एवं शिव कुमार ने निभाई।

बाल विवाह रोकथाम एवं संतुलित आहार के प्रति बच्चों और माताओं को किया जागरूक

तोशाम, 21 अप्रैल महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा उपमंडल के तोशाम और केरु दोनों ब्लॉक में बाल विवाह रोकथाम एवं संतुलित आहार के प्रति बच्चों और माताओं को जागरूक किया गया। गांव पटौदी के वीर शाहीद रिछपाल राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय स्तर पर बाल विवाह की रोकथाम एवं संतुलित आहार के महत्व के प्रति जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम पोषण पखवाड़ा के अंतर्गत आयोजित किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित किशोरियों को बाल विवाह के दुष्प्रभावों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। वहीं उन्हें इसके प्रति सतर्क रहने के लिए प्रेरित किया गया।

निगम व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम ने फैक्ट्री में की छापामारी

नितिन सिंगला जगधरी यमुनानगर। सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगाने को लेकर नगर निगम ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई की। निगम व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की संयुक्त टीम ने शहर के तेजली रोड स्थित एक फैक्ट्री में छापा मारकर बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित पॉलीथिन बरामद की। जांच करने पर 15 बैग में लगभग 375 किलोग्राम पॉलिथीन मिली। जिस पर नगर निगम द्वारा फैक्ट्री संचालक का 25 हजार रुपये का चालान किया



और बरामद पॉलिथीन को जप्त किया। यह कार्रवाई नगर निगम आयुक्त महाबीर प्रसाद के निर्देशों पर की गई। सिंगल यूज प्लास्टिक पर

रोक लगाने को लेकर निगम आयुक्त महाबीर प्रसाद के निर्देशों पर जोन एक में सीएसआई हरजीत सिंह व जोन दो में सीएसआई विनोद

पॉलीथिन बरामद शहर के तेजली रोड स्थित एक फैक्ट्री में छापा मारकर बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित पॉलीथिन बरामद की

बेनीवाल की टीम में गठित की हुई है। मंगलवार को निगम की टीम को तेजली रोड स्थित दक्ष फैब्रिक्स फैक्ट्री में प्रतिबंधित पॉलिथीन होने

कृमि मुक्ति अभियान का शुभारम्भ, हजारों बच्चों को दी गई एलबेन्डाजोल

टीम एक्शन इंडिया मनीष कुमार अम्बाला: राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के उपलक्ष्य में सिविल सर्जन डॉ रेनु बेरी व उप सिविल सर्जन (स्कूल हेल्थ) डॉ बलजिन्द्र कौर ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल प्रेम नगर अम्बाला शहर व तुलसी पब्लिक स्कूल अम्बाला शहर में

विद्यार्थियों को एलबेन्डाजोल की गोलीयां खिलाकर कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया। इस मौके पर जिले में सरकारी व निजी स्कूलों के साथ-साथ सभी तकनीकी संस्थानों, आंगनवाड़ी सेंटर, भट्टो व निमाणार्थीन स्थलों पर लगभग



3 लाख 53 हजार 050 (92.51 प्रतिशत) विद्यार्थियों व बच्चों को एलबेन्डाजोल की गोली खिलाई गई। इस मौके पर जिला किशोर स्वास्थ्य डॉ नेहा कौशिक ने बताया कि प्रजनन महिलाएं (20 वर्ष से 24 वर्ष की)

लगभग 19736 को भी दवाई खिलाई गई। सिविल सर्जन डॉ रेनु बेरी ने बताया कि यदि किसी कारण वश यह गोली खाने से रह गए है तो उन्हें 5 मई 2026 को मॉपअप राउंड के दौरान गोली खिलाई जाएगी।

गेहूं खरीद व उठान कार्य में किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं होगी बर्दाश्त: नेहा सिंह

टीम एक्शन इंडिया गोहाना (सोनीपत)। जिले में चल रही गेहूं खरीद प्रक्रिया को सुचारू, पारदर्शी एवं समयबद्ध बनाने के उद्देश्य से उपायुक्त नेहा सिंह ने मंगलवार को गोहाना अनाज मंडी का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मंडी में पहुंच रही गेहूं की फसल की खरीद, उठान, बायोमेट्रिक सत्यापन, श्रमिक व्यवस्था, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम तथा ई-खरीद पोर्टल से संबंधित सभी व्यवस्थाओं का गहनता से निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उपायुक्त ने मंडी में मौजूद किसानों से भी बातचीत कर उनकी समस्याओं की जानकारी ली और मौके पर ही अधिकारियों को समस्याओं के त्वरित समाधान के



निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन किसानों की उपज का समय पर और सुगमता से खरीद सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है तथा इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही या ढिलाई को किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए कि मंडी में आने वाली प्रत्येक किसान की फसल की समय पर खरीद सुनिश्चित की जाए तथा उठान कार्य

में तेजी लाई जाए, ताकि किसानों को अपनी उपज को लेकर किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। उपायुक्त ने कहा कि खरीद एजेंसियां, मार्केट कमेटी, वेयरहाउसिंग एजेंसियां और ट्रांसपोर्ट कॉन्टेनर आपसी समन्वय स्थापित कर कार्य करें, जिससे पूरी प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित हो सके। उपायुक्त ने कहा कि गेहूं के उठान में देरी किसी भी सूरत में

बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने ट्रांसपोर्ट कॉन्टेनरों को निर्देश दिए कि पर्याप्त संख्या में वाहनों की उपलब्धता सुनिश्चित करें और निर्धारित समय सीमा के भीतर गेहूं का उठान कर उसे गोदामों तक पहुंचाया जाए। यदि किसी भी कॉन्टेनर द्वारा लापरवाही बरती जाती है तो उसके खिलाफ पेनल्टी, नोटिस जारी करने सहित ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई की

महिला आरक्षण बिल को लागू करने में देरी क्यों कर रही भाजपा सरकार: रमेश मलिक

महिला आरक्षण पर जनता को गुमराह कर रही भाजप: रमेश मलिक

पूछे सवाल

□ भाजपा परिसीमन और सीटों की संख्या बढ़ाने से जोड़कर लागू करने में अनावश्यक देरी कर रही

टीम एक्शन इंडिया पानीपत, (बिजेन्द्र सिंह)। जिला कांग्रेस कमेटी पानीपत ग्रामीण ने सेक्टर 25 ट्रांसपोर्ट नगर स्थित पानीपत ग्रामीण कार्यालय में मंगलवार को प्रेस वार्ता का आयोजन किया। जिसमें महिला आरक्षण से जुड़े मुद्दे पर कांग्रेस नेताओं ने तथ्यों के साथ जवाब दिया गया। इस दौरान जिला अध्यक्ष रमेश मलिक ने कहा कि कांग्रेस के समर्थन से महिला आरक्षण बिल (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) वर्ष 2023 में संसद द्वारा सर्वसम्मति से पारित हो चुका है। इसके बावजूद भाजपा इसे परिसीमन और सीटों की संख्या बढ़ाने से जोड़कर लागू करने में



अनावश्यक देरी कर रही है। कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मत है कि महिला आरक्षण को बिना किसी शर्त के लोकसभा की मौजूदा सीटों के आधार पर तुरंत लागू किया जाना चाहिए, ताकि महिलाओं को उनका 33 प्रतिशत आरक्षण का अधिकार मिल सके। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि भाजपा इस मुद्दे पर जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही है, जबकि कांग्रेस हमेशा से महिलाओं के सम्मान, अधिकार

और सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध रही है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने ही पंचायती राज संस्थाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं को देने का प्रावधान किया गया था और राज्यसभा में 2010 में पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने ही इस महिला आरक्षण बिल को पास किया था। उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में

जिला व ब्लाक स्तर पर व्यापक अभियान चलाकर इस विषय की सच्चाई जनता तक पहुंचाएगी और महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई को मजबूती से आगे बढ़ाएगी। इस अवसर पर प्रमुख रूप से सचिन कुड्डू, बिजेन्द्र कादियान, बलबीर बालमीकि, खुशीराम जागलान, कंवर सिंह छक्कर, शशि लुथरा, सुरभि शर्मा एडवोकेट, अंजु छोक्कर एडवोकेट व सुभाष भट्टला आदि मौजूद रहे।

नवीन जिन्दल फाउंडेशन ने 228 लोगों को पहुंचाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं

टीम एक्शन इंडिया दलबीर सिंह मलिक कुरुक्षेत्र : सांसद नवीन जिन्दल की पहल पर नवीन जिन्दल फाउंडेशन द्वारा संचालित मोबाइल मेडिकल यूनिट लगातार जनसेवा का कार्य कर रही है। इसी कड़ी में फाउंडेशन की दो मोबाइल मेडिकल यूनिट कुरुक्षेत्र शहर के वार्ड नंबर 3, कैलाश नगर और पास लगते गांव डेरा पुरबिया व सिरसमा में पहुंची, जहां लोगों ने निःशुल्क स्वास्थ्य जांच और उपचार का लाभ उठाया। दोनों



मोबाइल मेडिकल यूनिट की चिकित्सक टीम ने सभी निर्धारित स्थानों पर मरीजों की जांच कर उनकी स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार परामर्श दिया। इसके साथ ही जरूरतमंदों को आवश्यक दवाइयां निःशुल्क उपलब्ध करवाई गईं तथा मौके पर ही रक्त जांच की सुविधा भी प्रदान की गई। इस संबंध में जानकारी देते हुए डॉ. प्रमोद ने बताया कि आज सभी चारों शिविरों में 187 लोगों को निःशुल्क परामर्श और दवाइयां दी गईं।

शाहाबाद नगर पालिका की हाउस बैठक में 26 करोड़ का बजट पास

शाहबाद: (प्रदीप कुमार) नगर पालिका में हाउस 2026 /27 बजट पर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें शहर के विकास को लेकर कई बड़े फैसले लिए गए। बैठक में शाहबाद के विधायक रामकरण काला, डीएमसी और नगर पालिका चेयरमैन गुलशन क्वात्रा के नेतृत्व में करीब 26 करोड़ रुपये का बजट सर्वसम्मति से पास किया गया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि किसी भी वार्ड में विकास कार्यों की कमी नहीं रहने दी जाएगी। बैठक के दौरान डीएमसी ने बताया कि पिछली बैठक के एजेंडे का रिव्यू किया गया है और कई प्रोजेक्ट फिलहाल पाइपलाइन में हैं। मानसून से पहले शहर के नालों की सफाई के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही शाहबाद क्षेत्र में हर साल आने वाली बाढ़ की समस्या को देखते हुए उसकी स्थायी समाधान के लिए डीपीआर (डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट) तैयार करने को भी कहा गया है। नगर में चल रहे विकास कार्यों को गति देने के निर्देश देते हुए, अधिकारियों ने कहा कि जो भी प्रोजेक्ट लंबित है, उन्हें जल्द आगे



बढ़ाया जाए। इसके अलावा बाजारों और मुख्य मार्गों पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर सख्ती बरतने के आदेश भी जारी किए गए, ताकि आम जनता को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।विधायक रामकरण काला ने बताया कि इससे पहले चार हाउस बैठकों को रद्द करना पड़ा था, क्योंकि पार्षदों के बीच सहमति नहीं बन पाई थी। उन्होंने कहा कि पार्षदों की शिकायत थी कि उनकी बातों को सुना नहीं जा रहा था। इस पर अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि सभी पार्षदों से संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। उन्होंने आगे कहा कि सभी पार्षदों को विश्वास में लेकर 15 दिन का समय मांगा गया है, ताकि विकास कार्यों को सही दिशा में आगे बढ़ाया जा सके। विधायक

ने यह भी कहा कि शाहाबाद की जनता लंबे समय से विकास कार्यों को लेकर परेशान है, लेकिन अब हालात बदलेंगे। बैठक में कई विकास परियोजनाओं के टेेंडर जारी किए गए हैं और अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि इन कार्यों को जल्द शुरू किया जाए। साथ ही चेतावनी दी गई कि यदि कोई अधिकारी कार्य में लापरवाही बरतता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर नगर पालिका प्रधान डा गुलशन कुमार, नगर पालिका चेयरपर्सन भाविका क्वात्रा, दीपक आनंद,पार्षद रीतु रानी,कुसम रानी, मिनाक्षी शर्मा, विजय कलसी, नीरज मद्दु,इंशा , आरती गुप्त , हीरालाल, नवनीत कौर, अमृतलाल, डा प्रवीन शर्मा, पंकज सिंगला,अमित सिंगल, तारा मौजूद रहे।

किसानों की सुविधाओं पर फोकस, परखी व्यवस्थाएं

टीम एक्शन इंडिया मनीष कुमार अम्बाला: एफसीआई विभाग की कार्यकारी निदेशक जेसिथा लाजारस (आईएएस), खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के आयुक्त एवं सचिव डा. जे. गणेशन (आईएएस) तथा जीएम एफसीआई शरणदीप कौर बराड़ (आईएएस) व उपायुक्त अजय सिंह तोमर (आईएएस) ने अनाज मंडी अंबाला छावनी का दौरा करते हुए ई-खरीद पोर्टल के तहत जो कार्य जैसे गेहूं खरीद के लिए गेट पास, बायोमेट्रिक व अन्य कार्यों का बारीकी से जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने मंडी परिसर में पौधापोषण भी किया। यहां पहुंचने पर डीएम हैकड देवेंद्र सिंह, डीएफएससी निशांत राठी व अन्य



ने कार्यकारी निदेशक के साथ-साथ अन्य का पुष्प गुच्छ देकर अभिनंदन किया। कार्यकारी निदेशक ने इस दौरान मंडी में किसानों व आदृतियों की सुविधा के लिए जो व्यवस्थाएं यहां की गईं हैं उसकी संबंधित से जानकारी ली। इसके साथ-साथ उन्होंने गेहूं खरीद के लिए मंडी में जियो फेसिंग, ई-खरीद पोर्टल के तहत मंडी में गेहूं की आवक आने

जायजा

□ ई-खरीद पोर्टल के तहत जो कार्य जैसे गेहूं खरीद के लिए गेट पास, बायोमेट्रिक का बारीकी से जायजा लिया

ली। इस मौके पर डीएफसी निशांत राठी ने बताया कि अंबाला छावनी अनाज मंडी में गेहूं खरीद का कार्य सुचारू रूप से जारी है तथा ई-पोर्टल के तहत तमाम कार्यों को किया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि अंबाला छावनी अनाज मंडी में 1 लाख 38 हजार 800 क्विंटल गेहूं की आवक आ चुकी है।

नूंह में रिटायर्ड कर्मचारी संघ हरियाणा का धरना, प्रधानमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन

टीम एक्शन इंडिया नूंह मेवात (लियाकत अली)ः रिटायर्ड कर्मचारी संघ हरियाणा जिला नूंह के बैनर तले मंगलवार को जिला मुख्यालय पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरना-प्रदर्शन किया और उपायुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। जिला प्रधान फरियाद मोहम्मद ने बताया कि हाल ही में कुरुक्षेत्र में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया था कि देशभर में एक दिन सभी जिलों में सेवानिवृत्त कर्मचारियों की मांगों को लेकर प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। इसी के तहत



नूंह सहित पूरे देश में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। उन्होंने कहा कि उनकी प्रमुख मांग आठवें वेतन आयोग से जुड़ी है। संघ का कहना है कि सरकार रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन में किसी प्रकार की कटौती न करे। जैसे पूर्व वेतन आयोगों में पेंशनर्स

को लाभ दिया गया है, उसी प्रकार आठवें वेतन आयोग में भी सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पूरा लाभ मिलना चाहिए। धरने में पूर्व कर्मचारी कमल सिंह सहरावत ने कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा बेहद जरूरी है।



लोकतंत्र की ताकत उसके कानूनों की स्पष्टता और सटीकता में होती है: गुप्ता



टीम एक्शन इंडिया

नई दिल्ली: विधायी मसौदा-निर्माण लोकतांत्रिक शासन का मूल है; किसी कानून की सटीकता ही तय करती है कि वह अधिकारों की रक्षा कितनी प्रभावी ढंग से करता है, जवाबदेही सुनिश्चित करता है और आम नागरिकों के जीवन को कैसे प्रभावित करता है, यह बात दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेन्द्र गुप्ता ने आज दिल्ली विधान

सभा के दौरे पर आए 18 देशों के 43 प्रतिनिधियों के दल को संबोधित करते हुए कही। ये प्रतिनिधि बांग्लादेश, भूटान, ओमान, केन्या, श्रीलंका, फिलीपींस और तंजानिया सहित विभिन्न देशों से आए थे और लोकसभा सचिवालय के संसदीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान (प्राइड) द्वारा आयोजित 37वें अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। गुप्ता ने बताया कि विधानसभा परिसर को



एक विरासत स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां एक संग्रहालय बनाया जा रहा है जो विधानसभा की यात्रा को दर्शाएगा। इसके अलावा, इसके इतिहास को जनता तक पहुंचाने के लिए लाइट एंड साउंड शो की भी योजना बनाई जा रही है। विधानसभा अध्यक्ष ने अपने संबोधन में विधानसभा के ऐतिहासिक और संस्थागत महत्व का उल्लेख करते हुए बताया कि वर्तमान भवन, जो 1912 में बना,

पहले इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का मुख्यालय था और बाद में 1919 के भारत सरकार अधिनियम के तहत केंद्रीय विधान सभा के रूप में उपयोग हुआ। उन्होंने 24 अगस्त 1925 को विट्टलभाई पटेल के पहले भारतीय अध्यक्ष के रूप में चुने जाने को याद किया और इसे औपनिवेशिक शासन के दौरान विधायी स्वायत्तता की महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। महात्मा गांधी सहित कई राष्ट्रीय



नेताओं की इस भवन में उपस्थिति का जिक्र करते हुए गुप्ता ने कहा कि यह संस्था केवल शासन का केंद्र नहीं रही, बल्कि लोकतांत्रिक आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति का भी मंच रही है। कार्यक्रम के दौरान प्रतिनिधियों ने विधानसभा भवन का भ्रमण किया। उन्होंने विट्टलभाई पटेल पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाई गई और ह्वाएक शताब्दी यात्राह नामक कॉफी टेबल बुक का परिचय भी दिया

गया। इस पुस्तक की एक प्रति प्राइड के निदेशक राजकुमार को लोकसभा पुस्तकालय के लिए भेंट की गई। वर्तमान पहलों के बारे में जानकारी देते हुए गुप्ता ने बताया कि दिल्ली विधान सभा ने कार्यकुशलता, पारदर्शिता और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। अब विधानसभा पूरी तरह सौर ऊर्जा पर संचालित हो रही है।

शाहदरा में दवाओं की अवैध बिक्री के खिलाफ चला सघन अभियान

टीम एक्शन इंडिया

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार के ड्रग कंट्रोल विभाग ने शाहदरा, दिल्ली में दवाओं की अवैध बिक्री के विरुद्ध सफल प्रवर्तन कार्रवाई की। बिना वैध लाइसेंस दवाओं की अवैध बिक्री किए जाने संबंधी गुप्त सूचना के आधार पर ड्रग निरीक्षकों की एक टीम ने राशिद मार्केट, गांव खुरेजी, शाहदरा स्थित एक परिसर पर छापेमारी की। माननीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा, दिल्ली सरकार जनस्वास्थ्य की सुरक्षा तथा दवाओं की बिक्री को पूर्णतः कानून के अनुरूप सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। किसी भी प्रकार का उल्लंघन,



विशेषकर दवाओं की अवैध बिक्री या वितरण, पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हम सभी हितधारकों से नियामकीय मानकों का पालन करने तथा नागरिकों से सतर्क रहकर ऐसी किसी भी अनियमितता की सूचना देने की अपील करते हैं।

कार्रवाई के दौरान एक डिकॉय ग्राहक भेजा गया, जिसने बिना चिकित्सकीय पर्चे और बिना कैश मेमो के कई दवाइयाँ खरीदकर अवैध बिक्री की पुष्टि की। निरीक्षण के दौरान परिसर में अवैध रूप से दवाइयाँ बेचने और संचालित करते हुए पाया गया। आगे की जांच में यह सामने आया कि उक्त परिसर पूर्व में वैध ड्रग लाइसेंस के अंतर्गत संचालित हो रहा था, जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा सितंबर 2024 में निरस्त कर दिया गया था। इसके बावजूद परिसर में दवाओं का भंडारण एवं बिक्री जारी रखी गई, जो विधिक प्रावधानों का उल्लंघन है।

टीम एक्शन इंडिया

नई दिल्ली: दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय राजीव भवन में आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की पूर्व महिला अध्यक्ष शोभा ओझा ने संवाददाता सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए कहा कि महिला आरक्षण के नाम पर भाजपा सरकार संसद में परिसीमन संशोधन बिल लाई जिसको 2011 की जनगणना के आधार लागू करके भाजपा अपने छिपे हुए एजेंडे को पूरा करना चाहती थी, जो संसद में पूर्ण बहुमत न मिलने पर धराशाही हो गया। जबकि महिला आरक्षण बिल सितंबर 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से संसद के दोनों सदनों में कांग्रेस के समर्थन के साथ और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद पास किया



गया जिसमें यह कहा गया था कि 2021 में जाति जनगणना होगी और उसके उसके आधार पर सीटों का परिसीमन करके महिलाओं के आरक्षण दिया जाएगा। संवाददाता सम्मेलन में शोभा ओझा के साथ दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री डा नरेन्द्र नाथ, दिल्ली प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष पुष्पा सिंह, अ0भा0क0कमेटी के पूर्व सचिव सी.पी. मितल और कम्युनिकेशन

विभाग के वाईस चेयरमैन अनुज आत्रेय मौजूद थे। शोभा ओझा ने कहा कि केन्द्र की मोदी सरकार महिलाओं के आरक्षण की आड़ में परिसीमन के माध्यम से सत्ता पर एकाधिकार जमाने की जो साजिश रची थी, विपक्षी एकजुटता ने उसे विफल कर दिया क्योंकि कांग्रेस पार्टी पार्टी ने हमेशा लोकतंत्र और संविधान की रक्षा और महिला सशक्तिकरण

के लिए हमेशा अग्रसर होकर देशहित में काम किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा की मूलभूत विचारधारा हमेशा महिलाओं के विरुद्ध रही है, यही कारण रहा है आर.एस.एस. के 100 वर्षों के दौर में और हिन्दू महासभा या भाजपा संगठन में कभी किसी महिला को स्थायित्व का पद दिया है। इतिहास जानता है कि भाजपा ने हमेशा महिलाओं के साथ हुए अत्याचार करने वालों का समर्थन किया और महिला अधिकारों की अनदेखी की है, यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी महिला आरक्षण को 2034 में लागू करने की बात करते हैं। शोभा ओझा ने कहा कि 1989 में राजीव गांधी द्वारा पंचायतों में 33 प्रतिशत महिला आरक्षण लाकर महिलाओं की

भागीदारी सुनिश्चित करने में जो क्रांतिकारी कदम उठाया उसे 1992-93 में नरसिम्हा राव सरकार ने पंचायतों और नगर निकायों में लागू करके महिलाओं के लिए सत्ता में आरक्षण सुनिश्चित कर दिया। यह एक व्यापक व्यवस्था रही जिसमें दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग की महिलाओं को 33 प्रतिशत का आरक्षण मिला। 2017 में तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी ने महिला आरक्षण बिल लाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा और 2018 में कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को महिला आरक्षण बिल को संसद के उसी मानसून सत्र में पारित करवाने के लिए पत्र लिखा था।

निगम आयुक्त संजीव खिरवार ने दक्षिणी जोन क्षेत्रों का किया किया निरीक्षण

टीम एक्शन इंडिया

नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम आयुक्त संजीव खिरवार ने दक्षिणी जोन में व्यापक निरीक्षण किया, जिसमें चल रहे कार्यों और नागरिक सुविधाओं की समीक्षा की गई। निरीक्षण अभियान का मुख्य उद्देश्य मुख्यमंत्री विकास निधि (सीएमडीएफ) के अंतर्गत चल रहे कार्यों की प्रगति, डीसिल्टिंग कार्यों और स्वच्छता कर्मियों की समीक्षा रहा। निगम आयुक्त संजीव खिरवार ने ग्रीन पार्क और आसपास के क्षेत्रों में सीएमडीएफ के तहत चल रही कई सड़क परियोजनाओं का गहन निरीक्षण किया। इस अवसर पर दक्षिणी जोन उपायुक्त राकेश कुमार एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम भी मौजूद रही। इस दौरान चल रहे कार्यों की गुणवत्ता पर संतोष व्यक्त करते हुए, खिरवार ने इंजीनियरिंग विभाग को शेष परियोजनाओं में तेजी लाने के सख्त निर्देश दिए, ताकि आम जनता को



आवाजाही की सुविधा हो सके। मानसून की तैयारियों पर बल देते हुए, संजीव खिरवार ने गौतम नगर में नालों और पार्किंग स्थलों की सफाई का जायजा लिया। उन्होंने सभी डीसिल्टिंग गतिविधियों के लिए सख्त

दस्तावेजीकरण प्रक्रिया सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि पारदर्शिता और जवाबदेही बनी रहे। निगम आयुक्त ने इन कार्यों को शीघ्र पूरा करने की आवश्यकता पर जोर दिया, ताकि शहर की जल निकासी व्यवस्था पूरी

तरह सुचारु रह सके। संजीव खिरवार ने कहा कि "सभी लंबित डीसिल्टिंग और सड़क कार्य निर्धारित समयसीमा के भीतर बिना गुणवत्ता से समझौता किए पूरे किए जाएं।" आयुक्त महोदय ने परियोजनाओं के निष्पादन

में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया। खिरवार ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कर्मचारियों का उचित उपयोग सुनिश्चित किया जाए, ताकि

दक्षिणी जोन में स्वच्छता के मानकों में उल्लेखनीय सुधार हो सके। दिल्ली नगर निगम सभी नागरिकों के लिए सुरक्षित, स्वच्छ और बेहतर सड़कों को सुनिश्चित करने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है।

दिल्ली में सजेगा योगासन प्रतिभाओं का महासंगम, 2 मई से शुरू होगा टूर्नामेंट

टीम एक्शन इंडिया

नई दिल्ली: राजधानी के युवाओं में योग के प्रति उत्साह और इसे खेल के रूप में नई पहचान दिलाने के लिए 'दिल्ली स्टेट योगासन एसोसिएशन' ने कमर कस ली है। आगामी शनिवार, 2 मई 2026 को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक बाल विद्यालय, बादली के प्रांगण में 'एनुअल दिल्ली स्टेट योगासन स्पोर्ट्स टूर्नामेंट' का भव्य आयोजन किया जाएगा।

दिग्गज हस्तिना बढाएंगी शोभा
इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री रविन्द्र इन्द्राज सिंह शामिल होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिले के उप शिक्षा निदेशक वेद प्रकाश करेंगे।



आयोजन की गरिमा और तकनीकी बारीकियों को सुनिश्चित करने के लिए वरिष्ठ योग विशेषज्ञ डॉ. मधु भारद्वाज के नेतृत्व में एक विशेष

टीम तकनीकी संचालन संभालेगी, जिससे निर्णयों में पूरी पारदर्शिता बनी रहे।
तैयारियाँ अंतिम चरण में

एसोसिएशन के महासचिव और कार्यक्रम के संयोजक उत्तम आर्य ने बताया कि आयोजन को सफल बनाने के लिए बादली विद्यालय के प्रधानाचार्य जगमोहन के साथ समीक्षा बैठक की गई है। विद्यालय प्रशासन ने आयोजन के लिए सर्वश्रेष्ठ सुविधाएं देने का आश्वासन दिया है। "हमारा लक्ष्य योग को केवल व्यायाम तक सीमित न रखकर इसे एक प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में वैश्विक मंच पर स्थापित करना है।" -
उत्तम आर्य, महासचिव
प्रतियोगिता की मुख्य विशेषताएं
पंजीकरण: अब तक दिल्ली के 55 से अधिक स्कूलों के 400+ खिलाड़ियों ने अपना नाम दर्ज कराया है।

समान अवसर: लड़के और लड़कियों के लिए अलग-अलग पैल ल बनाए गए हैं ताकि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो सके।
नेशनल का टिकट: इस टूर्नामेंट के टॉप विजेता खिलाड़ी आगामी नेशनल योगासन स्पोर्ट्स टूर्नामेंट 2026 में दिल्ली का प्रतिनिधित्व करेंगे।
क्यों खास है यह आयोजन?
यह टूर्नामेंट न केवल खिलाड़ियों की शारीरिक क्षमता का परीक्षण करेगा, बल्कि उनके लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने का द्वार भी खोलेगा। दिल्ली स्टेट योगासन एसोसिएशन का यह प्रयास शहर के स्कूलों में योग के प्रति एक नई लहर पैदा करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।



नरेला अनाज मंडी के प्रधान सुरेश गर्ग को जन्मदिवस की बधाई देते हुए समाज सेवी कृष्ण प्रधान, उत्तरी विभाग सहमंत्री विहिप मनोज बंसल, महासचिव नरेला चेतना मंच मोहित गुप्ता, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अग्रसेन धाम कुंडली दीपक मंगला व भाजपा नेता राहुल सिंघल।

44 साल पहले अधिग्रहित हुई 10 एकड़ जमीन, पर आज तक नहीं नसीब हुआ वोकेशनल कॉलेज

टीम एक्शन इंडिया/महेंद्र सिंह
नई दिल्ली: सरकार विकास के बड़े-बड़े दावे करती है, लेकिन जमीनी हकीकत इसके उलट है। नरेला विधानसभा क्षेत्र के मामूरपुर गांव में इसकी जीती-जागती मिसाल देखने को मिलती है। यहाँ लाला जगन्नाथ बंसल मार्ग पर साल 1983 में सरकार ने एक वोकेशनल कॉलेज बनाने के लिए 10 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया था। मकसद था स्थानीय युवाओं को तकनीकी शिक्षा प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना, लेकिन अफसोस! चार दशक से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी यहाँ शिक्षा का मंदिर तो नहीं बना, अलबत्ता गंदगी और कूड़े का आंबा जरूर लग गया है।

शिक्षा के नाम पर मिली सिर्फ 'खाली जमीन'

1983 में जब इस जमीन का अधिग्रहण हुआ था, तब क्षेत्र के लोगों में उम्मीद जगी थी कि उनके बच्चों को घर के पास ही तकनीकी शिक्षा मिलेगी। लेकिन 44 वर्षों में कई सरकारें आईं और गईं, पर किसी ने भी इस



प्रोजेक्ट की सुध नहीं ली। आज हालत यह है कि जिस जमीन पर कॉलेज की भव्य इमारत होनी चाहिए थी, वहाँ एक ईंट तक नहीं लगी है।
युवाओं के भविष्य पर भारी 'आर्थिक बोझ'

कॉलेज न होने का खामियाजा मामूरपुर और आसपास के करीब 3 से 4 लाख लोगों को भुगतना पड़ रहा है। तकनीकी शिक्षा के लिए यहाँ के छात्रों को दिल्ली के दूर-दराज के इलाकों में जाना पड़ता है। इससे



हेमराज बंसल



जोगिन्दर दहिया



रामचन्द्र भारद्वाज

अभिभावकों पर 3-4 लाख रुपये सालाना का अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ता है। कई भेदावी छत्र तो खर्वे न उठा पाने के कारण बीच में ही पढ़ाई छोड़ देने को मजबूर हैं।
क्या कहते हैं क्षेत्र के जिम्मेदार लोग?

'न्याय नहीं, अन्याय हुआ है'

ब्राह्मण कल्याण समिति के अध्यक्ष जोगिन्दर दहिया ने इस पर कड़ा रोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि 40 साल से सिर्फ वादे और फाइलों ही चल रही हैं। जमीन खाली पड़ी है और बच्चों का भविष्य अधर में है। उन्होंने इसे शासन की घोर लापरवाही करार देते हुए कहा कि अब क्षेत्र की जनता और इंतजार नहीं करेगी।

लगा चुकी है, लेकिन शासन-प्रशासन की नींद नहीं टूट रही। उनका कहना है कि यह सरकारी नाकामी का सबसे बड़ा प्रमाण है।
'इच्छाशक्ति का घोर अभाव'
नरेला विकास संगठन के प्रधान हेमराज बंसल ने तंज करते हुए कहा कि युवा अगर तकनीकी रूप से दक्ष नहीं होंगे तो देश कैसे बढ़ेगा? 44 साल में एक ईंट न लगना यह दर्शाता है कि प्रशासन में इच्छाशक्ति की कमी है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर इसके लिए दोषी कौन है—सरकार की नीयत या धूल फाँकी फाइलें?
'घोर लापरवाही का विषय'
फेडरेशन ऑफ नरेला के अध्यक्ष जोगिन्दर दहिया ने इस पर कड़ा रोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि 40 साल से सिर्फ वादे और फाइलों ही चल रही हैं। जमीन खाली पड़ी है और बच्चों का भविष्य अधर में है। उन्होंने इसे शासन की घोर लापरवाही करार देते हुए कहा कि अब क्षेत्र की जनता और इंतजार नहीं करेगी।

नरेला में भगवान परशुराम जन्मोत्सव की धूम, भक्ति भजनों पर झूमे श्रद्धालु

श्री ब्राह्मण सभा द्वारा भव्य समारोह का आयोजन, पूर्व चेयरमैन मोहन भारद्वाज सहित कई गणमान्य रहे मौजूद



टीम एक्शन इंडिया

नई दिल्ली: अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर नरेला विधानसभा क्षेत्र में भगवान विष्णु जी के छठे अवतार भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव कार्यक्रम की श्रद्धा और हार्दिकता के साथ मनाया गया। रेलवे स्टेशन रोड स्थित नंदीमल धर्मशाला में श्री ब्राह्मण सभा (पंजी.) नरेला द्वारा आयोजित इस भव्य समारोह में न केवल ब्राह्मण समाज, बल्कि सर्व समाज के सैकड़ों लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। कार्यक्रम का कुशल नेतृत्व सभा के अध्यक्ष राजेश रामगोपाल शर्मा ने किया।

गणमान्यों ने की पुष्पांजलि
समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन और भगवान परशुराम जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन मोहन प्रसाद भारद्वाज, एक्शन इंडिया समूह के संपादक रवि भारद्वाज, निगम पार्षद दिनेश भारद्वाज, युवा समाजसेवी रवीश भारद्वाज और विनोद भारद्वाज उपस्थित रहे। अतिथियों ने भगवान परशुराम के आदर्शों पर चलने और



समाज में एकजुटता बनाए रखने का आह्वान किया।
सांस्कृतिक संस्था में भक्ति का अनूठा संगम
कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ रही, जिन्होंने उपस्थित जनसमूह को मंत्रमुग्ध कर दिया। हरियाणा से पधारे प्रसिद्ध कलाकार इशू गौड़, भजन सम्राट मणि राम अत्रि और युवा गायक दीपक कौशिक ने अपनी मधुर वाणी से भगवान परशुराम जी की वीरता और जीवन गाथा का बखान

किया। भजनों की लय पर श्रद्धालु झूमते और नृत्य करते नजर आए, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। राजेश रामगोपाल शर्मा, अध्यक्ष (श्री ब्राह्मण सभा) ने कहा कि समाज को संगठित करने और नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति से जोड़ने के उद्देश्य से यह आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है।
इनकी रही गरिमामयी उपस्थिति
इस भव्य आयोजन को सफल बनाने में श्री ब्राह्मण सभा के पदाधिकारी नंद कुमार, रमेश परासर

और जय भगवान शर्मा की विशेष भूमिका रही। साथ ही राजेंद्र प्रसाद शर्मा, बलदेव गौड़, किशोर वत्स, रामकिशन भारद्वाज, रजत शर्मा, दीन दयाल शर्मा, डॉ. महेंद्र वशिष्ठ, संदीप शर्मा, राजकुमार ठेकेदार और प्रतीक राजकुमार सहित क्षेत्र के अनेक गणमान्य व्यक्ति और सैकड़ों श्रद्धालु उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में सभी के लिए प्रसाद एवं भंडारे की व्यवस्था भी की गई थी।



मोहन प्रसाद भारद्वाज, पूर्व चेयरमैन, स्थायी समिति, दिल्ली नगर निगम: भगवान परशुराम न्याय के सर्वोच्च प्रतीक हैं। उन्होंने समाज को यह संदेश दिया कि अधर्म के विरुद्ध आवाज उठाना ही वास्तविक धर्म है।



रवि भारद्वाज (समूह संपादक, एक्शन इंडिया): भगवान परशुराम 'शस्त्र और शास्त्र' के अनूठे संगम हैं। उन्होंने अहंकारी सत्ता का दमन कर धरती को अत्याचार मुक्त किया। उनके सिद्धांत किसी एक वर्ग के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए प्रेरणास्रोत हैं।



राजेश रामगोपाल शर्मा (अध्यक्ष, श्री ब्राह्मण सभा): श्री शर्मा ने भगवान परशुराम को वेदों का ज्ञाता और महान तपस्वी बताते हुए कहा कि उनका जीवन हमें सिखाता है कि केवल ज्ञान पर्याप्त नहीं है, राष्ट्र और समाज की रक्षा के लिए शक्ति तथा सामर्थ्य का होना भी अनिवार्य है।



दिनेश भारद्वाज (निगम पार्षद): परशुराम जी त्याग की प्रतिमूर्ति थे, जिन्होंने संपूर्ण पृथ्वी को जीतकर भी उसे दान कर दिया। आज की युवा पीढ़ी को उनके जीवन से प्रेरणा लेकर अन्याय, भ्रष्टाचार और नशे जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ एकजुट होना चाहिए।

